www.dhyeyaias.com

जनवरी 2021 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारत में कोविड-19 का टीकाकरण

आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक

2 भारत-जापान संबंध एवं वृहद् एशिया

3 आगामी बजट में सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाने की आवश्यकता

4 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर : विकास का वाहक

5 समुद्री शैवाल : भोजन के समृद्ध स्रोत

6 भारत के अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत

7 हरित भवन : पर्यावरण के लिए अनुकूल

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7
साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल
जनवरी 2021 | अंक 03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ. ➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक ➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक ➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक ➢ आशुतोष सिंह
संपादक ➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग ➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक ➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक ➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक ➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास ➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति ➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक ➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक ➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office
ध्येय IAS®
most trusted since 2003
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14
- भारत में कोविड-19 का टीकाकरण : आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक
- भारत-जापान संबंध एवं वृहद् एशिया
- आगामी बजट में सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाने की आवश्यकता
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर : विकास का वाहक
- समुद्री शैवाल : भोजन के समृद्ध स्रोत
- भारत के अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत
- हरित भवन : पर्यावरण के लिए अनुकूल

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21
7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23
7 महत्वपूर्ण खबरें 24–29
7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30
7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31
7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS (Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारत में कोविड-19 का टीकाकरण : आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक

चर्चा का कारण

- भारत में कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हो गया है। कोरोना वायरस महामारी के अंधकार भरे दौर में भारत की कोविशील्ड (Covishield) वैक्सीन, उम्मीद की नई किरण बनकर आई हैं। इन टीकों की मदद से आने वाले महीनों में कोविड-19 की महामारी पर काबू पाने की उम्मीदें जगी है। गौरतलब है कि आज विश्व के तमाम देशों में कोविड-19 के कई टीकों को नियामक संस्थाओं से मंजूरी मिल चुकी है और उन्हें लगाने का अभियान शुरू हो चुका है।

परिचय

- भारत में किसी भी वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार ही होती है जिसकी सभी चरणों की समीक्षा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नामक सरकारी संस्था करती है। डीजीसीआई से हरी झंडी मिलने के बाद ही किसी वैक्सीन के बल्क निर्माण की अनुमति मिलती है। गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वॉलिटी कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन के बल्क निर्माण के मानक तैयार किए जाते हैं और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय-समय पर वैज्ञानिकों तथा विनियामक प्राधिकरणों के माध्यम से चेकिंग होती रहती है।
- भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने कोविड-19 के इलाज के लिए दो वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है। ये दो वैक्सीन हैं- कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जहां असल में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह भारत की अपनी वैक्सीन है जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है।
- कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी बना रही है। वहीं, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के साथ मिलकर बना रही है।
- सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनायी जा रही वैक्सीन कोविशील्ड; या भारत बायोटेक का टीका कोवैक्सिन; दोनों ही टीके तुलनात्मक रूप से सुरक्षित साबित हुए हैं और इनके ज्यादा रिएक्शन भी नहीं देखे गए हैं। कोविशील्ड, जिसकी दो खुराक लेने की जरूरत होगी, उसका अभी भारत में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अन्य देशों में हुए ट्रायल में इस वैक्सीन ने 62 प्रतिशत असर दिखाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने हाल ही में कहा था कि अगर दो डोज के बीच तीन महीने का अंतर रखा जाता है, तो कोविशील्ड 90 प्रतिशत तक प्रभावी हो जाती है। भारत बायोटेक ने भी अपनी कोवैक्सिन को लेकर भी ऐसे ही दावे किए हैं और कहा है कि ट्रायल में इस टीके ने कम से कम 60 प्रतिशत असर दिखाया है।
- सरकार का लक्ष्य जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का है और इसे विश्व का 'सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान' भी कहा जा रहा है।

भारतीय टीकों की प्रभावशीलता

- कोविशील्ड का विकास कॉमन कोल्ड एडेनेवायरस से किया गया है। चिम्पांजी को संक्रमित करने वाले इस वायरस में बदलाव किए गए हैं, ताकि मनुष्यों को संक्रमित न कर सके। साथ ही वैक्सीन का 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 23,745 लोगों पर परीक्षण किया गया है। जबकि कोवैक्सीन का विकास भारतीय चिकित्सा परिषद (आइसीएमआर) और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने संयुक्त रूप से किया है। इसके निर्माण में मृत कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है, ताकि वह लोगों को नुकसान न पहुंचाए. जानकारों के मुताबिक यह वैक्सीन शरीर में प्रवेश करने के बाद कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करती है।
- दोनों ही वैक्सीनों की एफिकेसी यानी प्रभावकारिता को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन दोनों वैक्सीन में एक अंतर है जिसे लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनी चिंता जता रहे हैं।
- भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी जारी है और इफिकेसी डेटा अब तक उपलब्ध नहीं है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है।
- इसके अतिरिक्त कई वैज्ञानिकों ने कोवैक्सीन को अप्रूवल दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये नियामक के ही मापदंडों पर खरी नहीं उतरती।
- चूंकि भारत दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऐसे में अगर केवल एक स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की प्रतीकात्मक उपलब्धि जताने के लिए ही किसी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, तो इससे भारत को

फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि, बिना वैज्ञानिक नियामक प्रक्रिया के टीके को स्वीकृति देने से भारत की छवि को गहरा धक्का लग सकता है। ये बात खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि दवाओं से इतर, टीके स्वस्थ लोगों को लगाए जाते हैं और टीकाकरण अभियान काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आम लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आशंका इस बात की है कि अब भारत को भी रूस और चीन के ही दर्जे में रखा जा सकता है। उसकी वैक्सीन को ब्रिक्स देशों जैसा टीका बताकर, ये कहते हुए खारिज किया जा सकता है कि उसने स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की होड़ में बिना टीके के प्रभाव के आंकड़ों के ही उसे मंजूरी दे दी।

भारत में वैक्सीन की उपलब्धता

- भारत ने अपने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में अगस्त 2021 तक, प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सिन टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जैसी कंपनियों की मजबूत उत्पादन क्षमता को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा पहले चरण के टीकाकरण के लिए वैक्सीन जुटाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
- कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 70 करोड़ टीकों के उत्पादन तक बढ़ाने में जुटी है। इसके अलावा स्पुतनिक, नोवावैक्स और जायकोव-डी, जिनका भारत में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, उनकी करोड़ों खुराक भी भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित की जा सकती है।
- अगर सरकार टीकाकरण अभियान को कई महीनों में बांटती है, और दूसरे टीकों को भी हरी झंडी मिलती है, तो भारत में पहले चरण के टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन जुटाना मुश्किल नहीं होगा।

कोविड-19 वैक्सीन सबसे पहले किन्हें मिल रही है?

- सरकार द्वारा प्रकाशित दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों, फरंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से अधिक आयु के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से कम आयु के उन लोगों को दी जाएगी जिनको अन्य बीमारियां हैं। इसके बाद देश के बाकी लोगों को इसकी उपलब्धता के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर 50 साल से अधिक आयु के लोगों के समूह में भी विभाजन किया जा सकता है। इसमें 60 साल से अधिक आयु के लोगों का समूह और 50-60 साल आयु के लोगों का समूह बनाया जा सकता है। टीकाकरण के पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका देने की योजना है।

चुनौतियाँ

- 1.3 अरब की आबादी वाले देश में लोगों को टीकाकरण की प्रगति और उसके लाभ के बारे में सही समय पर सही जानकारी देना चुनौती है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों का कहना है कि पहली बार लाखों वयस्कों सहित अरबों लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना सरकार के सामने एक असाधारण चुनौती होगी।
- वैक्सीन को बिना लंबे ट्रायल के बाद देने को लेकर भी लोगों को सुरक्षा की चिंता होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों, नकारात्मक खबरों और टीके के असर को लेकर भी कई गलत धारणाएं बनाई जा सकती हैं।
- सरकार के दिशानिर्देशों में कहा गया है, कोविड-19 वैक्सीन के लेबल पर शायद वैक्सीन वायल मॉनिटर्स (वीवीएम) और एक्स्पायरी की तारीख न हो। ऐसे में वैक्सीन लगवाने वाले हतोत्साहित हो सकते हैं।
- विश्लेषकों का सवाल है कि उस मेडिकल कचरे के निपटारे को लेकर क्या किया जाएगा जो इस टीकाकरण अभियान से बड़े स्तर पर निकलेगा?
- इन सबके अलावा भारत में आम तौर पर होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए करीब 40 लाख डॉक्टर और नर्सों की जरूरत होती है। लेकिन, कोविड-19 के टीकाकरण के लिए और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ग्रामीण भारत तक इन संसाधनों का विस्तार कैसे होगा।

आगे की राह

- अगर देश भर में फैले 29 हजार टीकाकरण केंद्रों में प्रतिदिन लगभग 200 लोगों को वैक्सीन दी सके, तो भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान केवल दो महीनों में ही खत्म हो सकता है। भारत की नियामक व्यवस्था को लेकर विश्व में जो छवि है उसे देखते हुए, आज दुनिया को भारत की वैक्सीन की बेहद सख्त जरूरत है। अत: भारत की सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जैसी कंपनियों की मजबूत उत्पादन क्षमता को देखते हुए। भारत सरकार द्वारा पहले चरण के टीकाकरण के लिए वैक्सीन जुटाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
- भारत की नियामक व्यवस्था को लेकर विश्व में जो छवि है उसे देखते हुए, आज दुनिया को भारत की वैक्सीन की बेहद सख्त जरूरत है। चर्चा कीजिये।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. भारत की ड्रग नियामक व्यवस्था को लेकर विश्व में जो छवि है उसे देखते हुए, आज दुनिया को भारत की वैक्सीन की बेहद जरूरत है। चर्चा कीजिये ।

02 भारत–जापान संबंध एवं वृहद् एशिया

चर्चा का कारण

- वर्ष 2020 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजों आबे ने खराब स्वास्थ्य की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल के वर्षों में शिंजों आबे के नेतृत्व और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के चलते भारत जापान साझेदारी पहले से कहीं अधिक गहरी और मजबूत हुई है।

परिचय

- जापान के उत्तर-युद्ध काल के राजनीतिक इतिहास में, उसका कोई प्रधानमंत्री वैश्विक मीडिया, राजनीतिक, राजनयिक और आम जनता के आकर्षण का इतना केंद्र नहीं रहा है, जितना कि शिंजो आबे अपने कार्यकाल और विशेष रूप से अपना पद अकस्मात छोड़ने के बाद भी सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
- भारत और जापान के बीच मैत्री का एक लंबा इतिहास है जो आध्यात्मिक सोच में समानता तथा मजबूत सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित है। दोनों आधुनिक देशों ने पुराने संबंध की सकारात्मक विरासत को जारी रखा है, जो लोकतंत्र, व्यक्तिगत आजादी तथा कानून के शासन में विश्वास के साझे मूल्यों से सुदृढ़ हुआ है। वर्षों से दोनों देशों ने इन मूल्यों को सुहढ़ किया है तथा सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों के आधार पर एक साझेदारी का निर्माण किया है। आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा जापान एशिया का सबसे खुशहाल देश में से एक है।
- भारत द्वारा "लुक ईस्ट" नीति की पहल करने के साथ ही भारत-जापान संबंध में एक उठान प्रारम्भ हो गया था, लेकिन हाल के वर्षों में भारत सरकार की "एक्ट ईस्ट" नीति की परिकल्पना में और ऊँचाइयाँ आई।

आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग

- आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संपूरकताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। (I) जापान की वृद्ध होती आबादी (23 प्रतिशत 65 साल से अधिक आयु के) तथा भारत का गतिशील युवा वर्ग (50 प्रतिशत से अधिक 25 साल की आयु से कम); (ii) भारत के समृद्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधन तथा जापान की उन्नत प्रौद्योगिकी; (iii) भारत की सेवाओं के क्षेत्र में शक्तिशाली स्थिति और विनिर्माण के क्षेत्र में जापान की उत्कृष्टता; और (iv) निवेश के लिए जापान की अतिरेक पूंजी तथा मध्यम वर्ग की वजह से भारत के विशाल एवं बढ़ते बाजार।

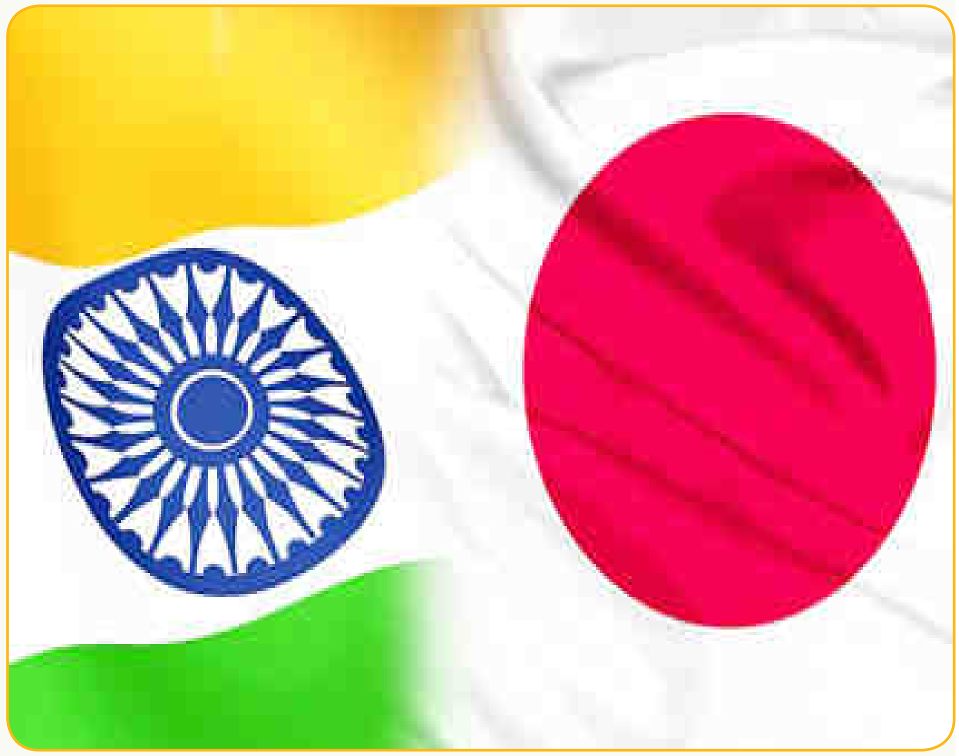

- एशिया की दो अर्थव्यवस्था के बीच विद्यमान स्पष्ट संपूरकताओं को देखते हुए भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों में विकास की प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं। अनेक कारणों की वजह से भारत में जापान की रूचि बढ़ रही है जिसमें भारत का विशाल एवं बढ़ता बाजार तथा इसके संसाधन, विशेष रूप से मानव संसाधन शामिल हैं। ऐतिहासिक भारत - जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर तथा अगस्त, 20 से इसके कार्यान्वयन से दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के विकास की गति और तेज होने की उम्मीद है।

जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन

- शिंजो आबे की पहल के चलते भारत में बुलेट ट्रेन चलने का रास्ता साफ हुआ। अगर बात बुलेट ट्रेन को लेकर हुए करार की करें तो इसे भारत-जापान संबंधों का शिखर माना जा सकता है। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के एक सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शिंजो आबे ने जो करार किया था वह भी कमाल का था।
- जापान दूसरे देशों को जिस दर पर ऋण देता है, उससे काफी कम दर पर भारत को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जरूरी राशि मुहैया कराएगा। ऋण वापसी की मियाद भी 25 वर्षों की जगह 50 वर्ष रखी गयी है। यानी करार हर तरह से भारत के पक्ष में हुआ। शिंजो आबे

विश्व के उन नेताओं में रहे, जो वैश्विक समृद्धि की दिशा में भारत को भी एक ग्लोबल पावर के रूप में ही देखते थे।

- भारत में रहने वाले जापानी नागरिक भारत के उज्जवल भविष्य को लेकर बेहद आशावादी हैं। ये जापानी होंडा सिएल कार, होंडा मोटरसाइकिल, मारुति, फुजी फोटो फिल्मस, डेंसो सेल्ज लिमिटेड, डाइकिन श्रीराम एयरकंडशिनिंग, डेंसो इंडिया लिमिटेड समेत लगभग दो दर्जन जापानी कंपनियों के भारत के विभिन्न भागों में स्थित दफ्तरों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं।

सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक समानता

- जापान के लोग भगवान बुद्ध के ही अनेकों पीढ़ियों से अनुयायी तो हैं ही, ये भारतभूमि को पूजनीय मानते हैं। ये मानते हैं कि भगवान बौद्ध का जीवन समाज से अन्याय को दूर करने के लिए समर्पित था। उनकी करुणा भावना ने ही उन्हें विश्व भर के करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। इन जापानियों में भी भारतीय संस्कार होते हैं। ये भारतीयों की तरह ही मितव्ययी हैं।

हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत-जापान

- चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी 'यथास्थिति' को एकतरफा बदलने की कोशिशों व तनाव बढ़ाने वाली किसी भी गतिविधि का कड़ा विरोध किया है, साथ ही मुक्त व खुले समुद्री क्षेत्र को अहम बताया। दरअसल, कोरोना महामारी की आड़ में चीन ने दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी लद्दाख में सैन्य आक्रमकता बढ़ाई है, जिसने वैश्विक चिंताओं को बढ़ाया है। इसके बाद भारत और जापान लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं और साझा चुनौतियों से निपटने को लेकर सहयोग बढ़ा रहे हैं। सितंबर 2020 में दोनों देशों ने एक दूसरे की सेनाओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस तक पहुंच मुहैया कराने को लेकर समझौता किया था।
- भारत की एक्ट ईस्ट नीति को देखते हुए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसे सहयोग को विकसित करने की बात कही गई है, जिससे हिंद व प्रशांत क्षेत्र को सभी के लिए समान अवसरों वाला बनाने में मदद मिले। इसके अतिरिक्त भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों (एनएसजी) के समूह में जापान सदस्य बनाने की जुगत में लगा है। गौरतलब है कि अमेरिका के मजबूत समर्थन के बावजूद चीन के विरोध की वजह से भारत अभी तक एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया है।
- विश्लेषकों के मुताबिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए 'यूएस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क' दस्तावेज में कहा गया है कि भारत सुरक्षा मामलों पर अमेरिका का पंसदीदा साझेदार है। सामरिक मुद्दों पर दोनों देशों की बढ़ती एकता और साझा समझ ऐसे समय पर आई है, जब दोनों देशों को ही इसकी जरूरत है। जापान प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे अहम साझेदार है और उसे उत्तर कोरिया की उकसाने वाली कारवाई का लगातार सामना करना पड़ रहा है, जबकि चीन भी इस क्षेत्र में लगातार अपनी घुसपैठ मजबूत करने के लिये प्रयासरत है। ऐसे में भारत निर्बाध और समृद्ध हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करने में प्रतिबद्ध है।
- विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन की आक्रामकता की वृद्धि के परिणामस्वरूप क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) अधिक सक्रिय हुआ है।

आगे की राह

- भारत के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को हर संभव प्रयास करने होंगे, ताकि जापान से अधिक से अधिक बुद्ध-सर्किट के पर्यटक भारत आएं। जापान से लाखों पर्यटक श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के बुद्ध तीर्थस्थलों में जाते हैं। इन पर्यटकों के एक बड़े हिस्से को हमें बोधगया-राजगृह-सारनाथ-वाराणसी में भी लाना होगा।
- एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर(एएजीसी) की शुरुआत होना महत्वपूर्ण है। यह भारत, जापान और अफ्रीका के कई देशों के साथ आर्थिक करार है। इस पहलकदमी की अप्रतिम विशेषता इसका सचेत रूप लोकान्मुखी होना है। एएजीसी के चार मुख्य कारक हैं: विकास और सहयोग की परियोजना, गुणवत्तापूर्ण संरचना और संस्थागत कनेक्टिविटी, क्षमता और कौशल विस्तार तथा लोगों से लोगों की साझेदारी। ये चारों संपूरक कारक दोनों महादेशों में संवृद्धि और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने वाले हैं।
- अमेरिका और चीन की तुलना में भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार बहुत कम है ऐसे में भारत को 'स्किल इंडिया प्रोग्राम तथा 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों के तहत जापान के सहयोग से द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत-जापान किस प्रकार अपने सम्बन्धों को और मजबूत बना सकते हैं। चर्चा कीजिये।

03 आगामी बजट में सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाने की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- संसद का बजट सत्र आगामी दिनों में आयोजित होने जा रहा है। यह कोविड-19 के बाद का पहला बजट होगा। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी, 2020 को केरल में सामने आया था। लेकिन इसका जिक्र न तो पिछले आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20) में हुआ और न ही केंद्रीय बजट 2020 में।
- संभवतः उस समय इस बारे में ये अंदाजा नहीं था कि इस महामारी का प्रभाव इतना भयावह होगा। बीते साल कोरोना संकट ने वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया है साथ ही सामाजिक असमानताओं को भी बड़ा दिया है। इसलिए उम्मीद है कि आगामी बजट में सामाजिक क्षेत्र विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बंधित पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

परिचय

- गौरतलब है कि भारत 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में सामाजिक क्षेत्र के विकास, लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
- परन्तु भारत में असमानताएँ समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और कोविड-19 ने उन्हें और बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में, सामाजिक क्षेत्र के खर्च और वितरण प्रणालियों में दक्षता पर ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि देश ने कुछ हद तक बिजली, सड़क और पानी के सम्बन्ध में प्रगति की है लेकिन सामाजिक क्षेत्र में और निवेश करना आवश्यक है।

भारतीय सामाजिक क्षेत्र की स्थिति

- अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास की तुलना में सामाजिक क्षेत्र में भारत की प्रगति बहुत धीमी रही है। भारत के मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दो प्राथमिक और आवश्यक कारक निम्न स्तर पर हैं जो हैं-स्वास्थ्य और शिक्षा।

- ध्यावत है कि वर्तमान में भारत मानव विकास सूचकांक पर 189 देशों में से 131 रैंक पर है।
- पिछले कुछ वर्षों के सामाजिक क्षेत्र के खर्च पर एक नजर डालने से पता चलता है कि 2014-15 से 2019-20 के दौरान कुल जीडीपी में शिक्षा पर खर्च 2.8-3 प्रतिशत के आसपास रहा है। वहीँ स्वास्थ्य के मामले में, यह व्यय 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गया।
- विडम्बना यह है भारत का सामाजिक क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, लैंगिक असमतानाओं का सामना करते हैं साथ ही सार्वजनिक व्यय और वितरण प्रणालियों में उत्पन्न अनियमितताएँ, विषमताएँ, लैंगिक खाई को और चौड़ा करती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र

- वर्तमान और भविष्य की महामारियों से बचाव करने के लिए स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से विकास के लिए स्वास्थ्य ढांचे में ज्यादा निवेश होना चाहिए। महामारी के चलते गैर-कोरोना मरीजों के अलावा भी हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, इससे निपटने के लिए एक मजबूत और प्रभावी पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूरी है।
- कोरोना संकट ने हमें ये एहसास कराया है कि क्यों हमें एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत है, जिसे पिछले कई बजटों में कमतर आंका गया था।
- कोविड-19 के अनुभव से यह भी पता चला है कि महामारी के दौरान हम गैर-महामारी से संबंधित रोगियों की उपेक्षा करते हैं।
- स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि और सभी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना आवश्यक है।
- स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की कम उपलब्धता ने इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। ज्यादातर लोगों को इसका खामियाजा निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के रूप में भुगतना पड़ता है और वे भारी भरकम कर्ज में डूब जाते हैं।
- NFHS-5 रिपोर्ट से पता चलता है कि कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में मामूली रूप से कम हो गया है और कुछ अन्य राज्यों में खराब हो गया है, हालांकि 2015-16 और 2019-20 के बीच कुछ अन्य संकेतक बेहतर हुए हैं। कुल मिलाकर भारतीय समाज में 35 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं।

- कुपोषण के अलावा, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। कुपोषण और मोटापा दोनों को कम करने के लिए सुलभ और सस्ती विविध भोजन का सेवन महत्वपूर्ण है।
- इसलिए ICDS और अन्य पोषण कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि देश के लिए भूख और कुपोषण की अनदेखी की लागत कहीं अधिक नुकसानदायक होगी

शिक्षा क्षेत्र

- मानव के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है। महामारी ने शिक्षा में असमानताओं को बढ़ाया है और डिजिटल खाई को और बड़ा किया है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और श्रम बाजार में असमानताओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कई समितियों ने सिफारिश की है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का 6 प्रतिशत होना चाहिए।

सामाजिक क्षेत्र के उन्नयन में सरकार के प्रयास

- पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने रसोई गैस (उज्ज्वला योजना), बिजली (सौभाग्य योजना) प्रदान करने के साथ-साथ स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त आवास, वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने की दिशा में अच्छा काम किया है। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की भी सुविधा दी थी। विश्लेषकों का मानना है कि इन कार्यक्रमों से कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं सामाजिक दशा में सकारात्मक बदलाव आए हैं। जानकारों का मानना है कि इन पहलों को जारी रखना वर्तमान समय की आवश्यकता है।

- प्रवासी श्रमिक महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित थे और उनके पास कोई सुरक्षा निधि नहीं था। अतएव शहरी गरीबों और प्रवासियों के सुविधाओं के लिए, रोजगार गारंटी योजना की तरह ही एक सुरक्षा स्कीम होना आवश्यक है। हालांकि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से भारत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 50,000 करोड़ रूपये के खर्च का प्रावधान रखा गया हें पहलों को जारी रखना वर्तमान समय की आवश्यकता है
- सरकार को बेहतर नीतियों और कार्यान्वयन के साथ सामाजिक क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र के पुनरोद्धार में राज्यों के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रमुख व्यय उनके द्वारा मिलते हैं।
- 15 वें वित्त आयोग ने भी उल्लेख किया है कि स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.1 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। आयोग राज्यों को स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने सम्बंधित कुछ प्रोत्साहन का सुझाव भी दे सकता है।

आगे की राह

- हमारा भारतीय समाज स्वास्थ्य और शिक्षा में धीमी प्रगति करके आगे नहीं बढ़ सकता है। वैश्विक शक्ति बनने के इच्छुक भारत को एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी सामाजिक क्षेत्र में विकास करना चाहिए क्योंकि यह एसडीजी प्राप्त करने, असमानताओं को कम करने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बेहतर कार्यान्वयन और परिणामों के साथ उच्च सामाजिक क्षेत्र के वित्तपोषण की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 महामारी ने दर्शाया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सरकार को व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

04 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर : विकास का वाहक

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Western Dedicated Freight Corridor-WDFC) के रेवाड़ी-मदार (Rewari-Madar section) खंड को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा-भाऊपुर सेक्शन (इस कॉरिडोर के निर्माण में विश्व बैंक सहयोग कर रहा है) का उद्घाटन किया था। इनके निर्माण से रेलवे देश में माल ढुलाई के क्षेत्र में आमूल बदलाव की तैयारी कर रहा है।

परिचय

- देश के सभी कोनों को जोड़ने के लिए राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डेन ट्राईएंगल) का निर्माण किया गया, उसी तरह पूरे देश को सिर्फ माल ढुलाई के लिए समर्पित रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा भी स्वर्णिम चतुर्भुज और दो डायगोनल का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। वर्ष 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था।
- साल 2010 के बजट में तत्कालीन रेल मंत्री ने चार नए कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया था।

1. ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (कोलकाता से मुंबई) करीब 1976 किमी.
2. नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर (दिल्ली-चेन्नई) करीब 2173 किमी.
3. ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (खड़गपुर-विजयवाड़ा) करीब 1100 किमी.
4. साउदर्न कॉरिडोर (चेन्नई-गोवा) करीब 899 किमी। ये चार गलियारे अभी भी योजना के चरण में हैं। इस परियोजना में पूरे देश में छह माल ढुलाई गलियारों का निर्माण किया जा रहा है।

- देश में मालगाड़ियों की गति को अब बढ़ाया जा रहा है, जो रफ्तार पहले 25 KM/PH थी अब उसे 90 KM/PH तक पहुंचाया जा रहा है। रेवाड़ी-मदार खंड के शुरू होने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी-मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ इलाके में स्थित विभिन्न उद्योगों को लाभ होगा और यह काठुवास में स्थित कॉनकोर के कंटेनर डिपो के बेहतर इस्तेमाल को भी संभव बनायेगा।

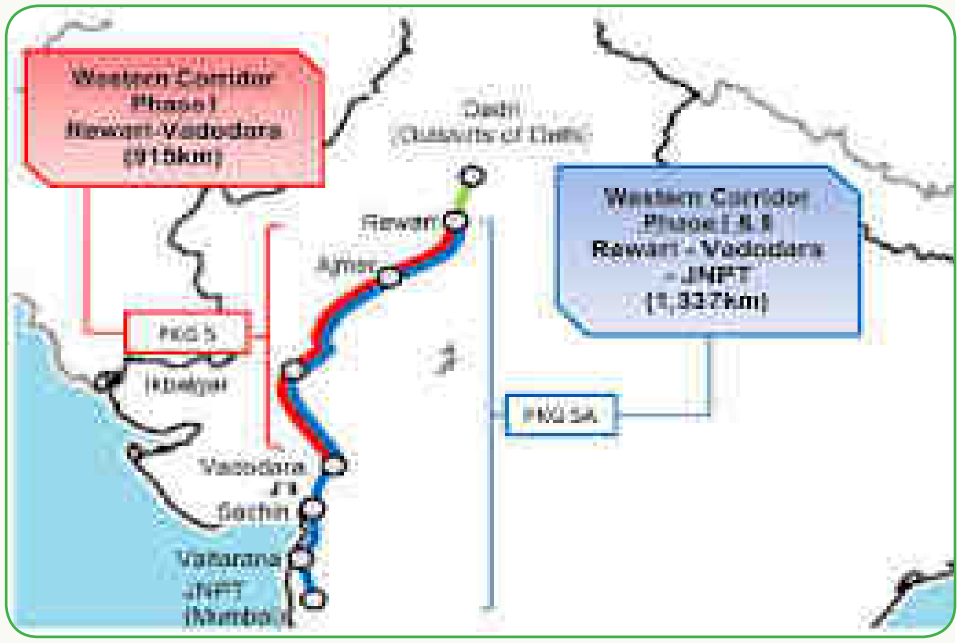

- रेवाड़ी -मदार खंड हरियाणा (लगभग 79 किलोमीटर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी) और राजस्थान (लगभग 227 किलोमीटर, जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर) में स्थित है। इस कॉरिडोर के निर्माण में जापान का सहयोग रहा है। पिछले कुछ वर्षों से नई रेल लाइन, लाइनों के चौड़ीकरण, बिजलीकरण पर बड़ा निवेश हुआ है। इसके अतिरिक्त जल्द ही नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी भी रेलवे से जुड़ेगी।
- इसके अतिरिक्त करीब 351 किलोमीटर लंबा भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन 5750 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के एल्युमिनियम, सीसा, ताला समेत कई स्थानीय उद्योगों को फायदा मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से कानपुर-दिल्ली मेन लाइन पर ट्रैफिक भी काफी कम होगा।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है?

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ऐसी रेल लाइन से है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के आवागमन के लिए किया जाएगा। देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इनकी कुल लंबाई 3000 किलोमीटर है। इनका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के लिए होगा। दोनों परियोजनाओं के चालू होने से, न सिर्फ रेलवे को माल ढुलाई या फ्रेट परिवहन में अपनी बाजार हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि साथ ही यह माल ढुलाई की कारगर, विश्वसनीय, सुरक्षित एवं किफायती व्यवस्था की भी गारंटी होगी।
- माल ढुलाई से संबंधित इन दो कॉरिडोर्स के चालू होने से, परिवहन की इकाई लागत में कटौती होने, छोटे संगठन और प्रबंधन की कम लागत होने और ऊर्जा की कम खपत से रेलवे के परिचालनों में मूलभूत बदलाव आएगा।
- इसके लिए सरकार ने एक अलग कंपनी बनायी है- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड (DFCCIL), यह रेल मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका गठन 30 अक्टूबर 2006 को हुआ। इसमें DFCCIL की भूमिका इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रोवाइडर और इस कॉरिडोर के निर्माण, संचालन और रखरखाव की है। DFCCIL खुद डीएफसी पर इन मालगाड़ियों का संचालन करेगा और अंत में उन्हें रेलवे या अन्य ऑपरेटर को सौंप देगा।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों?

- आजादी के बाद 1950-51 में कुल माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा 83 फीसदी था, लेकिन 2011-12 तक यह घटकर 35 फीसदी तक आ गया। दूसरी तरफ देश में कुल सड़क जाल का महज आधा फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले नेशनल हाईवे के द्वारा कुल सड़क माल ढुलाई का 40 फीसदी हिस्सा जाता है। इसकी वजह से रेलवे में माल ढुलाई बढ़ाने के प्रयास के तहत यह बड़ा कदम उठाया गया।
- देश में बुनियादी ढांचे विकास पर अगले वर्षों में भारी निवेश की योजना है, उद्योगों का तेज विकास हो रहा है, बिजली की बढ़ती जरूरतों के लिए कोयले की ढुलाई लगातार बढ़ती जा रही है, इन सब वजहों से माल ढुलाई के लिए अलग से ऐसे लाइन के विकास की जरूरत महसूस हुई जिन पर सिर्फ मालगाड़ियां चलें ताकि किसी तरह का डिस्टर्बेंस न हो और माल तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सके।
- चूंकि मालगाड़ी की गति धीमी होती है। इसकी वजह यह है कि यात्री गाड़ियों को रास्ता देने के लिए मालगाड़ियों को रोका जाता है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से यह समस्या दूर होगी। मालगाड़ियों के लिए अलग रेल लाइन होने से उनकी रफ्तार बढ़ेगी। माल ढुलाई में कम वक्त लगेगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का करीब 60 फीसदी उत्तर प्रदेश में है। इसके पूरी तरह बन जाने पर प्रदेश के छोटे-बड़े उद्योग को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें कच्चे माल मंगाने में आसानी होगी। उन्हें तैयार उत्पाद को भी देश के अलग-अलग स्थानों पर जल्द भेजने में मदद मिलेगी।
- एक अनुमान के मुताबिक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से मालगाड़ी की स्पीड तीन गुना हो जाएगी। इससे माल गाड़ियां पहले से दो गुना सामान की ढुलाई कर सकेंगी। इस पर डबल डेकर मालगाड़ी चलाई जाएंगी।

लाभ

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई खर्च में भी कमी आएगी। इसका सीधा फायदा निर्यात को मिलेगा।
- विदेश में भारतीय उत्पादों की लागत में कमी आएगी, जिससे वे प्रतिस्पर्धा का बेहतर मुकाबला कर सकेंगी। इससे निवेश के लिए भारत को आकर्षक देश बनाने में भी मदद मिलेगी।
- इस प्रोजेक्ट से बंदरगाहों, निर्यातकों, आयातकों, शिपिंग लाइन, कंटेनर ऑपरेटर आदि को काफी फायदा होगा।
- भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन और GSM आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा, यानी इससे मालगाड़ियों की ट्रैकिंग भी की जाएगी।
- इस कॉरिडोर से बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा, क्योंकि माल ढुलाई वाले वाहन की जरूरत कम होगी। Ernset -Young के एक अनुमान के अनुसार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से पहले 30 साल में ही करीब 45 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा।
- इसके अतिरिक्त इस नए फ्रेट रेल मार्ग से भारतीय रेलवे की मुख्य लाइनों पर अधिक संख्या में यात्री गाड़ियाँ चलाई जा सकेंगी, जिससे भारतीय ट्रेनें अधिक समयबद्ध हो सकेंगी।
- इस कॉरिडोर से कई शहरों में विकास केंद्रों और कई क्षेत्रों का विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

आगे की राह

- आधारभूत क्षेत्रों के आधुनिकीकरण से संबद्ध क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित होगा जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को जल्द ही राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। कोविड-19 संकट के बावजूद भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं, जिससे जानकारों को उम्मीद है कि भारत 2025 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।
- आबादी के बढ़ते दवाब और धन की कमी के चलते पटरियों की लंबाई बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत सरकार अपेक्षा के अनुरूप निवेश नहीं आकर्षित कर पायी है। इसलिए माल ढुलाई के मामले में भारतीय रेलवे सड़क मार्ग के मुकाबले तेजी से पिछड़ रही है। ऐसे में रेल मंत्रालय को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नियोजन एवं विकास, वित्तीय साधनों की तैनाती, निर्माण, रखरखाव और संचालन आदि गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

Topic:

- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके लाभों को गिनाइए। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे "इकोनॉमी के पावर बूस्टर" के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? चर्चा कीजिये।

05 समुद्री शैवाल : भोजन के समृद्ध स्रोत

चर्चा का कारण

- भारत समुद्री शैवाल (seaweed) की बढ़ती मांग को पूरी करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा किसानों को समुद्री शैवाल लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि सागर तट के पास उगने वाले समुद्री शैवाल भोजन का स्थायी स्रोत बनने के साथ जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मददगार हैं।

परिचय

- पम्बन द्वीप और जैव विविधता से समृद्ध मन्नार की खाड़ी में पारंपरिक उपचार के लिए सदियों से समुद्री शैवाल निकाले जाते हैं। स्थानीय लोग ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी प्राकृतिक समुद्री वनस्पतियां एकत्र करते रहे हैं। भारत अब इन्हीं गांवों को समुद्री शैवाल की खेती के लिए मॉडल के तौर पर विकसित कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर सालाना 8 फीसद की दर से बढ़ रहा है।
- भारतीय शोधकर्ता लंबे समय से टिकाऊ खेती के तौर पर समुद्री शैवाल की खेती अपनाने की वकालत करते रहे हैं। उष्णकटिबंधीय मौसम, उथले पानी और पोषक तत्वों की भरमार के कारण भारत के लंबे सागर तट इसके लिए आदर्श हैं।
- गुजरात और तमिलनाडु के सागर क्षेत्र में इनकी समृद्ध जैव विविधता है। तमिलनाडु के 1,000 किलोमीटर लंबे सागर तट के पास ही करीब 282 तरह की शैवाल की प्रजातियां मिलती हैं। भारत में कुल मिलाकर 841 प्रजातियों के शैवाल मिलते हैं, हालांकि इनमें से कुछ प्रजातियों की ही खेती होती है।

समुद्री शैवाल एवं उनके लाभ

- समुद्री शैवाल तेजी से बढ़ने वाली शैवाल है। ये शैवाल सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेती हैं और समुद्री पानी से पौष्टिक तत्व और कार्बन डाईऑक्साइड। वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि समुद्री शैवाल जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं और कार्बन उत्सर्जन की भरपाई भी कर सकते हैं।

- समुद्री शैवाल में कई विटामिन और खनिज की भरपूर मात्रा होती है। इसलिए इसका सेवन एनीमिया और पोषण की कमी के इलाज में फायदेमंद हो सकता है। यह डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा है। इसमें काम्प्लेक्स शुगर होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता।
- शैवाल शाकाहारियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें प्रचुर प्रोटीन होता है। स्पिरुलिना में अंडे, मछली और मांस से ज्यादा प्रोटीन होता है। खाने योग्य समुद्री शैवाल शरीर की रोजाना की जरूरत का आयरन देता है। यह स्पिरुलिना के मामले में बिलकुल सच है, जिसमें अनाज और पालक के मुकाबले छह गुना आयरन है। यह एनीमिया या सामान्य कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है।
- खाने योग्य सिवार हाई ब्लड प्रेशर से लड़ने में मदद कर सकते हैं। यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप से लड़ने में मदद करता है। एरामे सीवीड में दूध के मुकाबले 15 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। साथ ही स्पिरुलिना और वेकैम ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के लिए या टूटी हुई हड्डी को ठीक करने में एरामे सीवीड खाने की सिफारिश की जाती है।
- समुद्री शैवाल की खेती का एक बड़ा हिस्सा खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है लेकिन इसके अर्क का इस्तेमाल कई तरह की चीजों में किया जाता है। चाहे वो टूथपेस्ट हो, कॉस्मेटिक हो, दवाइयां हो या फिर पालतू जानवरों के खाने में। इन सभी में हाइड्रोकोलॉयड्स होता है जोकि समुद्री शैवाल से ही आता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अब टेक्सटाइल्स और प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर, वॉटर कैप्सूल बनाने में और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के तौर पर भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर समुद्री शैवाल का उत्पादन इस समय अपने चरम पर है।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हैं, समुद्री शैवाल

- भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहां की 60 फीसद जमीन खेती के काम आती

है, लेकिन करीब 47 फीसद कृषियोग्य भूमि मिट्टी कटाव के कारण नष्ट हो रही है। मिट्टी को होने वाले इस नुकसान का करीब एक-तिहाई हिस्सा पानी से होने वाला कटाव है। मगर समुद्री शैवाल की खेती में पानी भी समाधान का हिस्सा हो सकता है।

- विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय कृषि में नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने अगले पाँच साल में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 8.7 करोड़ डॉलर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। गुजरात के ओखा बंदरगाह पर एक दशक तक प्रयोगशाला और फील्ड ट्रायल के बाद 1997 में समुद्री शैवाल को तमिलनाडु के मंडपम में बोया गया।
- धीरे-धीरे पाक-जलसंधि के इर्द-गिर्द 100 किलोमीटर (62 मील) लंबे तटक्षेत्र में सफलतापूर्वक इसकी खेती होने लगी। बड़े पैमाने पर शैवाल की खेती साल 2000 में शुरू हुई जब CSMCRI ने पेप्सिको को इसका लाइसेंस दिया। पेप्सिको की दिलचस्पी खाद्य फसल के रूप में इसकी खेती करने की नहीं थी, बल्कि वह कैरेगीनन का उत्पादन करना चाहती थी, जिसका इस्तेमाल खाने में, सौंदर्य सामग्रियों में और उद्योगों में होता है। इससे भारत में समुद्री शैवाल की वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा मिला
- एक्यूएग्री (AquAgri) पहली भारतीय कंपनी है जो समुद्री शैवाल की वाणिज्यिक खेती में उतरी। आज इस कंपनी के पास तमिलनाडु में 18 सेंटर हैं जहां 650 मछुआरों को रोजगार मिलता है। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं।
- शैवाल की खेती बढ़ने से तटीय समुदायों, खासकर महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर सकारात्मक असर पड़ा है। इससे उन्हें अपनी आर्थिक आजादी हासिल करने में मदद मिली है। करीब 100 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में देसी और विदेशी प्रजातियों के शैवाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए CSMCRI मत्स्य पालन मंत्रालय के साथ काम कर रहा है।

चुनौतियाँ

- शैवाल की खेती के कुछ पारिस्थितिकीय नुकसान भी हो सकते हैं। शैवाल के अनियंत्रित विकास से कैरिबियाई क्षेत्र में मूंगे की चट्टानों को नुकसान पहुँचा है।
- इन चट्टानों के पास रहने वाली कुछ मछलियां उन्हीं जगहों पर रहना पसंद करती हैं जहां शैवाल न हों। भारत के मन्नार की खाड़ी में कुरुसादाई द्वीप के पास भी मूंगे की चट्टानों को समुद्री शैवाल से नुकसान पहुँचने की खबर है।
- आसपास होने वाली खेती से समुद्री शैवाल यहाँ चले आए थे, हालांकि CSMCRI के अध्ययन में पाया गया कि करीब 77 वर्ग मीटर (828 वर्ग फुट) के एक छोटे से हिस्से में ही इसका असर था।

शैवाल के पारिस्थितिकीय लाभ

- समुद्री वनस्पतियों की खेती के फायदे इससे मिलने वाले पोषण तक सीमित नहीं हैं। ये प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) के जरिये भोजन तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे जमीन पर दूसरे पौधे करते हैं। मगर वास्तव में ये बड़े शैवाल (macro algae) हैं। समुद्री शैवाल कार्बन डाई-ऑक्साइड अवशोषित करते हैं, कार्बन को शर्करा में तब्दील करते हैं और पानी में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।
- पहले माना जाता था कि इन वनस्पतियों के समुद्र में विघटित होने पर उनमें जमा कार्बन मुक्त हो जाता है। लेकिन गहरे समुद्र में मृत शैवाल भारी मात्रा में मिले तो पता चला कि मृत होने पर ये शैवाल समुद्र की तलहटी तक चले जाते हैं और उनमें मौजूद कार्बन वहीं तलछट में कैद रहता है।
- विश्लेषकों के मुताबिक सी-वीड की खेती की पहचान कार्बन सिंक के रूप में की गई है जो जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने में मददगार हो सकती है। कार्बन इकट्ठा करने के अलावा, सी-वीड समुद्री भोजन की श्रृंखला बनाते हैं। पादप प्लवक (फाइटोप्लैंकटन) के साथ ये कई समुद्री जीवों के लिए आश्रय और भोजन मुहैया कराते हैं।

आगे की राह

- भारत तीन ओर से सुमुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में ब्लू इकोनॉमी पर फोकस बढ़ाकर देश की आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले समुद्र आधारित बिजनेस मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है, साथ ही संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने और समुद्री कचरे से निपटने के डायनामिक मॉडल पर काम करने की आवश्यकता है।
- पर्यावरण फिलहाल दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है ऐसे में ब्लू इकोनॉमी (ब्लू इकोनॉमी के तहत फोकस खनिज पदार्थों समेत समुद्री उत्पादों पर होता है।) को अपनाना इस नजरिये से भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग- कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।

प्र. समुद्री शैवाल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि क्या ब्लू इकोनॉमी पर फोकस बढ़ाकर देश की आर्थिक विकास को मजबूत किया जा सकता है?

06 भारत के अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत

संदर्भ

- किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी बुनियादी संरचना उसके सच्चे गौरव की बात होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बुनियादी संरचना क्षेत्र भारत की आधारशिला है और भारत के समग्र विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

परिचय

- इन्फ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए बेहतर संभावनाएं प्रदान करता है।
- इस क्षेत्र में बिजली, बंदरगाह, सड़क, रेलवे, दूरसंचार जैसे कई उप-समूह शामिल हैं। इस संदर्भ में एक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के कार्यक्रम को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) की शुरुआत की, जिसमें उसने 2024-25 तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर करीब 102 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई थी।
- क्योंकि वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के में बदलती जनसांख्यिकी रूपरेखा की आकांक्षाओं को देखते हुए नये बुनियादी संरचनाओं के विकास तथा पुराने बुनियादी संरचनाओं में सुधार वर्तमान समय की आवश्यकता है।

कैसे तय करें अवसंरचना का पैमाना?

- कोविड-19 महामारी ने भारत सरकार के सामने कुछ विकट चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आर्थिक विकास पांच साल के निचले स्तर पर है, बैंक ऋण अत्यधिक विवश नजर आ रहे हैं, निजी निवेश में भी गिरावट आई हैं, साथ ही बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी अभी तक परियोजना की विफलताओं से उबरने

की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच राजकोषीय तनाव स्पष्ट रूप से बढ़ा है।

- हालांकि, सरकारी व्यय में अभी केवल सड़क, प्रमुख राजमार्ग और रेलवे शामिल हैं, परन्तु अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी पानी और सीवेज, स्वच्छता, रसद और नवीकरण हेतु धन की आवश्यकता है। यहां कुछ उपाय प्रस्तुत किये गय हैं जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं जो बुनियादी संरचना उद्योग को बढ़त दे सकें-

निजी निवेश को बढ़ावा

- इसके लिए लंबित परियोजनाओं के पूरा करना होगा। इससे भारी मात्रा में निजी निवेश आएगा। यह दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है पहला किसी भी परियोजना के निष्पादन के लिए DBFOT अर्थात डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, संचालन और हस्तांतरण मोड को पुनर्जीवित करना और दूसरा आक्रामक परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से निवेश संसाधन जुटाना।
- इसके लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय जोखिमों को पूरी तरह से खत्म करने के साथ सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के जोखिम आवंटन के लिए रूपरेखा को पुनर्निर्मित करके परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

ओवरऑल द क्रेडिट इकोसिस्टम:

- परंपरागत रूप से, बुनियादी ढांचा क्षेत्र अपनी ऋण और वित्त जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ऋण पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। परन्तु, हाल ही में, और विशेष रूप से कोविड-19 के कारण, बैंकों ने उच्च संपत्ति दायित्व के बेमेल और संबंधित निष्पादन जोखिमों के कारण विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में, अपने कदम पीछे किए हैं।
- इसलिए, ऐसे परिदृश्य में, सरकार को या तो बॉण्ड की गारंटी के साथ आने की जरूरत है या परियोजनाओं के लिए ऋण निधि को बढ़ाने की, ताकि इस क्षेत्र के वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बॉण्ड बाजार का कायाकल्प हो सके।

हार्नेस नवीनतम प्रौद्योगिकी:

- यह काफी आश्चर्यजनक है कि भारत में बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक निर्माण परियोजनाएँ,

अब भी अत्याधुनिक परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर और उपकरणों को शामिल नहीं करती हैं, जिनसे अन्य देशों को अपनी परियोजनाओं को शीघ्र से समाप्त करने में मदद मिलती हैं।

- क्योंकि फास्ट-ट्रैकिंग परियोजनाओं के निर्माण में संवर्धित वास्तविकता (एआर), यूएवी और ड्रोन, 3 डी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (बीआईएम) जैसी तकनीकें काम आती हैं। उदाहरण के लिए, 5D BIM परियोजना हितधारकों को एक ईंट की नींव रखने से पहले एक गहन योजनाबद्ध संरचना की आभासी कल्पना समाने प्रस्तुत कर देता है। जिससे किसी भी परियोजना से सम्बंधित आगामी निर्णय लेने में आसानी हो जाती है।

मुख्य प्राथमिकताएं:

- यह महत्वपूर्ण है कि सरकार उन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और उपक्रमों की पहचान करे, ताकि संसाधनों को केवल उन तक ही सीमित कर सके, जो उस परियोजना से सम्बंधित हो उदाहरण के लिए, जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण करना, जिसके तहत सरकार ने 2024 तक हर घर में पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध किया है और साथ ही यह जल संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े अन्य सभी कार्यक्रमों को भी संभालेगी।
- यह कुशल दृष्टिकोण कई मंत्रालयों के संसाधनों को एक विलक्षण, मूर्त और प्राप्त लक्ष्य को पुनर्निर्देशित करने में मदद करेगा।
- इसके अलावा, सरकार को बड़ी फ्लैगशिप परियोजनाओं जैसे कि समर्पित माल गलियारों, नवी मुंबई हवाई अड्डे आदि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें 'राष्ट्रीय आयात परियोजनाओं' के रूप में चिह्नित करना चाहिए ताकि उनके कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक अलग समर्पित परियोजना निगरानी समूह बनाया जा सके।

अवसंरचना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है?

- अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है बुनियादी संरचना में सुधार होने से रोजगार के नये अवसर सृजित होते हैं। रोजगार के अवसर प्राप्त होने से लोगों की आय में वृद्धि होती है। इसलिए बुनियादी संरचना के निर्माण द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग निम्नलिखित 5 तरीकों से बढ़ाया जा सकता है-
- **निजी अंतिम उपभोग व्यय**-निजी अन्तिम उपभोग व्यय अर्थात् लोग अपने उपभोग व्यय में वृद्धि करें लेकिन वर्तमान समय में लोगों के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव है। बुनियादी संरचना में सुधार से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे जिससे लोगों के पास पूंजी आयेगी जिसके परिणामस्वरूप उपभोग बढ़ेगा
- **सरकारी अंतिम उपभोग व्यय**- सरकारी अन्तिम उपभोग व्यय अर्थात् सरकार अपने खर्च में वृद्धि करे। सरकार यदि बुनियादी ढ़ांचें में निवेश करती है तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है जिससे वित्तीय स्थिरता आती है।
- **सकल निश्चित निजी पूंजी निर्माण**- सकल निश्चित निजी पूंजी निर्माण अर्थात् इस क्षेत्र में निजी उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। निवेशकों में निवेश के लिए विश्वास बढ़ता है जिसके पश्चात् रोजगार सृजन में सहायता मिलती है और लोगों की वित्तीय स्रोत्रों तक पहुँच सुनिश्चित हो जाती है।
- **सकल निश्चित सार्वजनिक पूंजी निर्माण**- सकल निश्चित सार्वजनिक पूंजी निर्माण मद में सरकार द्वारा कोई कंपनी स्थापित की जाती है या किसी अवसंरचना का निर्माण किया जाता है या किसी अवसंरचना का निर्माण किया जाता है उदाहरण-किसी पुल/सेतु का निर्माण।
- **शुद्ध निर्यात**- इससे बैंकों में वित्तीय पूंजी बढ़ेगी, जिससे लोगों का इन संस्थानों में विश्वास बढ़ेगा, बेहतर परियोजना में निवेश से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे जीडीपी (GDP) में भी सुधार संभव है।

आगे की राह

- यदि भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बुनियादी संरचना में सुधार होगा, तो गुणवत्ता में भी सुधार होगा, इस प्रकार जीडीपी में भी वृद्धि होगी और आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ ही सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में आसानी होगी।
- वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था भी सामान्य स्थिति में वापस आने की कोशिश कर रही है हालांकि अनुमानित वृद्धि दर और निवेश, महामारी के कारण अल्पावधि में बाधित हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार द्वारा सही उपाय अपनाएँ जाते हैं तो इस क्षेत्र में जल्द ही तेजी आएगी।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. भारत सरकार को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी से सुधार हो?

07 हरित भवन : पर्यावरण के लिए अनुकूल

चर्चा का कारण

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के मुताबिक 2030 तक भारत के लिए जितनी इमारतों की जरूरत होगी, उसका 70 प्रतिशत हिस्सा बनना अभी बाकी है। अगर भारत इस विशाल मांग को पूरा करने के लिए पर्यावरण अनुकूल (ग्रीन) इमारतों के विचार को अपनाता है तो ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा। भारत में पर्यावरण अनुकूल इमारतों का बाजार अभी शुरुआती दौर में है और सिर्फ 5% इमारतों को ग्रीन इमारत का दर्जा मिला है।
- चूँकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की जंग में यहां की इमारतों के विकास और विस्तार की अहम भूमिका है। भारत की कुल ऊर्जा खपत में इमारतों का योगदान 40 प्रतिशत है और इसमें सालाना 8 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो रही है।
- इसलिए अगर परंपरागत तौर-तरीके से इमारतें बनती रहीं तो 2050 तक उत्सर्जन में इमारतों का योगदान 70 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह पर्यावरण से जुड़ी भारत की महत्वाकांक्षा के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न होगा।

ग्रीन इमारतों की आवश्यकता

- भारत में ग्रीन इमारतों का समर्थन करने के कई कारण हैं। इनमें सबसे पहली और शायद सबसे साफ वजह पर्यावरण पर उनके असर से जुड़ी है, खास-तौर पर ऊर्जा की मांग।
- परंपरागत इमारतों के मुकाबले ग्रीन इमारतों में ऊर्जा पर कम लागत आती है। हालांकि ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण और डिजाइन पर शुरुआत में ज्यादा लागत आती है लेकिन लंबे वक्त में कम रखरखाव की लागत और ऊर्जा की कम खपत की वजह से इस लागत की भरपाई हो जाती है।
- इसका एक उदाहरण है सीआईआई गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर इस इमारत को बनाने में परंपरागत इमारत के मुकाबले 18 प्रतिशत ज्यादा खर्च हुआ। लेकिन सात साल के छोटे से ही समय में इमारत की लागत की भरपाई हो गई।

- महामारी और उसके दुष्प्रभावों को देखते हुए रिहायशी घरों में रहने वालों के साथ-साथ काम-काज की जगह के लिए भी ग्रीन इमारतों का आकर्षण बढ़ गया है।
- कोविड के पश्चात उम्मीद की जा रही है कि लोग अपनी सेहत, तंदुरुस्ती और आराम के लिए और भी सतर्क हो जाएंगे। लोग ऐसी इमारतों में रहना पसंद करेंगे जिनमें बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम, सूर्य की पर्याप्त रोशनी और ताजा पानी की उपलब्धता होगी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक घर के भीतर खराब हवा-पानी की वजह से होने वाली सांस और फेफड़े से जुड़ी बीमारियां मौत की पांच बड़ी वजहों में से तीन के लिए जिम्मेदार हैं।
- इसके अलावा भारत में ग्रीन इमारतों की जरूरत को मजबूत बनाने ण्0वाली एक और महत्वपूर्ण वजह है भारत के पर्यावरण से जुड़ी आर्थिक बहाली में इसकी मुख्य भूमिका। कोविड के बाद इस बात पर एक राय है कि "बेहतर कल बनाया जाए" और अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में निवेश किया जाए जो रोजगार उत्पन्न करने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल विकास कर सकें। ग्रीन इमारत इस लक्ष्य को पूरा करने का एक अच्छा माध्यम है।

सरकार और बैंक की भूमिका

- भारत में पर्यावरण अनुकूल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फिलहाल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और निर्माण के लिए फंड की कमी है ग्रीन इमारत बनाने में ये सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है और इसके लिए रेगुलेशन की जरूरत है।
- कई सरकारी योजनाओं में इस सेक्टर को शुरुआती प्रोत्साहन मुहैया कराने का महत्वपूर्ण सामर्थ्य है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की तारीफ की गई है। साथ ही रोजगार निर्माण में भी इसकी सराहना की गई है।
- साथ ही अगर इस योजना का इस्तेमाल पर्यावरण अनुकूल इमारत बनाने में किया जाए तो ये अर्थव्यवस्था पर और भी सकारात्मक असर डालेगी।
- क्योंकि पीएमएवाई और इको-निवास संहिता यानी ग्रीन हाउसिंग स्कीम मिलकर देश में ग्रीन रिहायशी इमारतों के सेक्टर को काफी बढ़ावा दे सकती हैं।
- इसके अलावा राज्य स्तर पर कई राज्य सरकारों ने गृह परियोजनाओं के लिए बढ़ी हुई फ्लोर टू एरिया रेशियो (एफएआर) का वादा किया है जिससे बिल्डर ग्रीन बिल्डिंग बनाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकें।

- अमेरिकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (यूएसजीबीसी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रोत्साहनों की वजह से तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य देश में सबसे ज्यादा ग्रीन इमारतें बनाने में सफल हुए हैं।
- इन राज्य सरकारों की कामयाबी से पर्यावरण अनुकूल निर्माण को प्रोत्साहन मिला है और दूसरी राज्य सरकारों को भी इनका अनुसरण करने का प्रोत्साहन मिला है।
- 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2024-25 तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारत में 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत है। सरकार के समर्थन के अलावा ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के लिए निवेश मुहैया कराने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- ग्रीन परियोजना बनाने में वित्तीय समर्थन बहुत बड़ी रुकावट है क्योंकि उनके निर्माण और डिजाइन की शुरुआती लागत ज्यादा होती है। ग्रीन परियोजनाओं में लंबे वक्त तक निवेश की जरूरत होती है और बैंक ग्रीन इमारतों के निर्माण के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर इस तरह का निवेश मुहैया करा सकते हैं। भारत में एसबीआई, यस बैंक, एग्जिम बैंक और एक्सिस बैंक कुछ ऐसे बैंक हैं जो ग्रीन बॉन्ड जारी करते हैं।
- बैंक होम लोन की ब्याज दर को इमारत की ग्रीन रेटिंग के साथ जोड़ सकते हैं। वो बिल्डर को प्रोत्साहन देने के लिए कम ब्याज दर पर कंस्ट्रक्शन लोन की भी पेशकश कर सकते हैं। प्रदर्शन को परखने और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत में भी सब्सिडी वाले इंश्योरेंस मॉडल की शुरुआत की जा सकती है (चीन के कुछ शहरों में इसे अपनाया गया है)।
- इस मॉडल के तहत, कंस्ट्रक्शन से पहले बिल्डर एक ग्रीन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, क्वालिटी का वादा करता है और तय मानकों का पालन करता है। इसके बाद बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर ग्रीन क्रेडिट जारी करता है।

- फिर अगर वादा किए गए मानकों को पूरा नहीं किया जाता है तो पैसा देने या मरम्मत की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। इस मॉडल के कामयाब होने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मुहैया कराने और बिल्डर के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए उसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

निष्कर्ष

- कंस्ट्रक्शन उद्योग भारत में सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में से एक है। कंस्ट्रक्शन उद्योग 9.2 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 10 प्रतिशत का योगदान करता है। इस तरह रिहायशी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा संभावना है। "सब के लिए घर" कार्यक्रम के तहत 2 करोड़ शहरी और 1 करोड़ ग्रामीण घरों की जरूरत है।
- घर बनाने को लेकर कंपनियां भी खुश हैं। कई कंपनियों ने तो "कार्बन न्यूट्रल" का वादा भी किया है। इसलिए भारत में ग्रीन रिहायशी और व्यावसायिक निर्माण को लेकर बेहद मजबूत कारोबारी मामला बनता है।
- मौजूदा मंदी को देखते हुए 2030 तक पर्यावरण अनुकूल इमारतें रिन्यूएबल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 90 लाख हुनरमंद नौकरियां मुहैया कराकर आर्थिक विकास और "बेहतर कल" के विशेषाधिकार का मजबूत जरिया बन सकती हैं।
- बैंकिंग सेक्टर के साथ सहयोग करके सरकार ग्रीन कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रोत्साहन मुहैया करा सकती है और इस मामले में भारत को उसका सामर्थ्य हासिल करने में मदद कर सकती है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:
- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

Topic:
- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. हरित भवनों या ग्रीन इमारतों का संक्षिप्त परिचय देते हुए लाभों एवं चुनौतियों को रेखांकित करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में सीजेआई एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जानवरों की क्रूरता की रोकथाम (केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स, 2017) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकर से क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत वर्ष 2017 में अधिसूचित नियमों को वापस लेने या संशोधित करने के लिए कहा है।

2. वर्ष 2017 में अधिसूचित नियम

- केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स, 2017 अधिकारियों को मवेशी परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने और पशुओं को गौशालाओं या गौ-आश्रमों में भेजने की अनुमति देते हैं।
- इस अधिनियम के मुताबिक अगर किसी पशु के साथ अत्याचार किया जाता है तो आरोपी के अपराध साबित होने से पहले ही पशु को जब्त कर लिया जाता है किन्तु आरोपी दोषमुक्त पाया जाता है तो पशुओं को उसके मालिक को वापस कर दिया जाता है।

3. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अनुसार पशुओं के प्रति क्रूरता करने वालों को दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा इस एक्ट द्वारा 'पशु कल्याण बोर्ड' की भी स्थापना की गई। इस बोर्ड की शक्तियों और कार्यों को संबंधित प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित किया गया। साथ ही अधिनियम में वैज्ञानिक रिसर्च के लिए जानवरों पर किए जाने वाले प्रयोगों के लिए भी दिशानिर्देश दिए गए हैं।
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 29 के अनुसार यदि कोई पशु मालिक इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी पाया जाता है, तो अदालत, उस पर दंड या जुर्माना लगा सकती है, साथ ही वो पीड़ित जानवर को सरकार द्वारा जब्त कर लेने का आदेश भी दे सकती है। हालांकि उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी पूर्वत दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य द्वारा अथवा स्वामी के चरित्र के बारे में या अन्यथा पशु के प्रति बर्ताव के बारे में यह दर्शित नहीं कर दिया जाता कि यदि उस पशु को स्वामी के पास छोड़ दिया जाएगा तो उसके प्रति और भी अधिक क्रूरता होना संभाव्य है।
- दूसरी तरफ 2017 के नियमों के चलते, पशुधन मालिक या पशु व्यापारी सिर्फ क्रूरता के आरोप के चलते ही, और दोषी पाए जाने से पहले ही, अपने पशुओं को खो देता है।

4. सर्वोच्च न्यायालय का मत

- पशुओं की बिक्री करना पशुओं के लिए हानिकारक नहीं है। किसी पशु को बेचने का अर्थ ये नहीं है कि पशु को हानि पहुंचाई जा रही है, बल्कि इससे उसके मालिक को आजीविका मिलती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये नियम कानून के विपरीत है, अगर सरकार इसके प्रावधानों को नहीं हटाती है तो अदालत इसे रोक सकती है। सरकार को इस नियम यानी जब्ती के नियम को वापस ले लेना चाहिए और बाद में उचित संशोधन करके इसे वापस सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए।

02 भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी

1. चर्चा का कारण

- भारत ने दो स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। कोरोना से जारी वैश्विक जंग में वैक्सीन के स्तर पर भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन (एचसीक्यू) दवा की तरह दुनिया के कई देश अब भारत से कोरोना वैक्सीन लेने की उम्मीद कर रहे हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- भारत सरकार ने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी के तहत अब इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप केंद्र सरकार की निगरानी में बांग्लादेश भेजी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना से जंग में भारत की तरफ से 50 से अधिक देशों को पैरासीटामोल, एचसीक्यू व अन्य दवाइयों की आपूर्ति की गई।
- ब्राजील व मैक्सिको जैसे देशों से भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन को लेकर पूछताछ की गई है। कई अन्य देश भारत में औपचारिक तौर पर वैक्सीन लगने की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश पहले से ही भारतीय वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान भी भारतीय फार्मा जगत से संपर्क की कोशिश में है।
- बांग्लादेश के अलावा वैक्सीन श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों को भी भेजी जाएगी। विश्लेषकों के मुताबिक देश में वैक्सीन लगने की औपचारिक शुरुआत के बाद भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने वाले देशों में निर्यात की इजाजत दी जा सकती है।

3. भारत-चीन के बीच प्रतिस्पर्धा

- दुनिया को कोविड के टीके मुहैया कराने की तैयारी का एक सिरा कूटनीति से भी जुड़ता दिख रहा है, जहां भारत और चीन के बीच मुकाबला हो सकता है । चीन अपनी छवि को बेहतर करने के लिए वैक्सीन डिप्लोमैसी का सहारा ले रहा है। साथ ही वह, 'अमेरिका फर्स्ट' के वैक्सीन नेशनलिज्म का जवाब भी देना चाहता है। इसके लिए वह कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक देशों में उसके टीकों का इस्तेमाल हो।
- इसके इतर बांग्लादेश ने भारतीय वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रॉयल पर सहमति जताई है। चीन ने सिनोवैक बॉयोटेक लिमिटेड द्वारा बनाए गए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर बांग्लादेश को वित्तीय सहारा देने की पेशकश की लेकिन बांग्लादेश ने इसे अस्वीकार कर दिया।
- वैक्सीन डिप्लोमेसी संशोधित अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक अनोखा अवसर प्रदान करती है। वैक्सीन की मांग वैश्विक है, कुछ ही देशों में इसका विकास किया जा रहा है। व्यापक स्तर पर उत्पादन की सुविधाएं भारत और चीन के समान बहुत कम ही देशों के पास हैं।

4. भारत का वैश्विक देशों में बढ़ता कद

- भारत कोवैक्स एंड गावी (covax and gavi) के नेतृत्व वाले समूह के 189 देशों, जिनमें अमेरिका शामिल नहीं है, द्वारा की गई एक अन्य पहल में भी भागीदार है। उनका उद्देश्य 2021 के अंत तक 2 बिलियन खुराकों की खरीद करना है, इसका आधा हिस्सा पूरी दुनिया के निम्न आय वर्ग के देशों को दिया जाएगा, जिसे वे अपने यहां के उच्च जोखिम और आरक्षित समूहों विशेषकर स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करने के लिए वितरित करेंगे।
- विश्व गुरु के एक अंग के रूप में भारत कोविड-19 की वैक्सीनों, उनके उपयोग, वितरण, विशेषकर विकासशील देशों में अपनी क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकी को साझा करने का मजबूत राजनयिक प्रयास करता है। भारत की उत्पादन सुविधाएं ने उसे वैक्सीन के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है।

03 राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति–2020

1. चर्चा का कारण

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अगले दशक में वैज्ञानिक शोध एवं विकास के मामले में देश को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में लाने को लक्ष्य कर बनायी गई नई विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- महत्वपूर्ण मानव संसाधन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित एवं पोषित करने के साथ-साथ उन्हें इस क्षेत्र में बनाए रखने के लिए इस नीति के अंतर्गत 'जन-केंद्रित' पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया है।
- नई नीति में, हर पाँच साल में पूर्णकालिक समतुल्य शोधकर्ताओं की संख्या, शोध एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय (जीईआरडी) और जीईआरडी में निजी क्षेत्र के योगदान को दोगुना करने पर भी बल दिया गया है।
- विश्लेषकों के मुताबिक ये तमाम प्रयास अगले दशक के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित करने में मददगार होंगे, और देश को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

3. समावेशी भावना के मूल सिद्धांतों पर आधारित

- यह नीति विकेंद्रीकरण, साक्ष्य-आधारित, नीचे से ऊपर केंद्रित दृष्टिकोण और समावेशी भावना के मूल सिद्धांतों पर आधारित है।
- नई नीति के मसौदे को तैयार करने में देशभर में व्यापक विचार-विमर्श किया गया है, जिसमें पहली बार राज्यों की भागीदारी भी शामिल है। मसौदा निर्माण प्रक्रिया के दौरान करीब 300 चरणों में परामर्श किया गया है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, आयु वर्ग, लिंग, शैक्षिक पृष्ठभूमि व आर्थिक स्तर के 40 हजार से अधिक साझेदार शामिल रहे हैं।
- इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्रित एक बेहतर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके लघु, मध्यम और दीर्घकालिक मिशन मोड वाली परियोजनाओं के माध्यम से बड़ा बदलाव लाना है, जो व्यक्ति और संगठन दोनों स्तर पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है।

4. लैंगिक समता पर बल

- मसौदा नीति में कहा गया है कि समलैंगिक, ट्रांसजेंडर समुदाय आदि (एलजीबीटीक्यू प्लस) को भी लैंगिक समता संवाद में शामिल किया जाएगा। इसमें समुदाय के सदस्यों के अधिकारों की हिफाजत का विशेष प्रावधान किया जाएगा और एसटीआई में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- एसटीआईपी एक राष्ट्रीय एसटीआई (Science, Technology & Innovation) केंद्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो एसटीआई वातावरण में निर्मित सभी तरह के डेटा का केंद्रीय संग्रहकर्ता के तौर पर काम करेगा। यह सभी तरह की वित्तीय योजनाओं, कार्यक्रमों, अनुदानों और प्रोत्साहन राशि के लिए एक खुला केंद्रीकृत डेटाबेस मंच होगा।

5. एसटीआई शिक्षा को बेहतर बनाना

- नीति में एसटीआई शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों के बारे में भी उल्लेख है। एसटीआई शिक्षा को सभी स्तर पर समावेशी बनाया जाएगा और इसे अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक जोड़ा जाएगा तथा इस तरह कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की प्रक्रिया के जरिए समाज का विकास होगा।
- एसटीआई वातावरण के वित्तीय दायरे का विस्तार करने के लक्ष्य के साथ केंद्र के प्रत्येक मंत्रालय, राज्य के प्रत्येक विभाग और स्थानीय सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां तथा स्टार्ट-अप एसटीआई गतिविधियों के लिए न्यूनतम बजट आवंटन के साथ एसटीआई इकाई स्थापित करेंगे।

6. आगे की राह

- कोविड-19 को देखते हुए बदलते समय के साथ नई समस्याएं उभर रही हैं, जिन्हें केवल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। यह नीति इस दिशा में उठाया गया एक प्रभावी कदम है।

04 यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (यूएसटीआर) की रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (USTR) ने भारत, इटली और तुर्की की ओर से लगाए गए डिजिटल सर्विस टैक्स (DSTs) को अमेरिकी कंपनियों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया है। साथ ही USTR ने कहा कि यह डिजिटल टैक्स अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

2. परिचय

- USTR ने डिजिटल टैक्स लगाने पर इन देशों को प्रतिरोधी टैरिफ का सामना करने की चेतावनी दी है।
- USTR इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि फ्रांस, भारत, इटली और तुर्की की ओर से अमेरिकी की दिग्गज टेक कंपनियों गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजन पर लगाया गया डिजिटल सर्विस टैक्स भेदभावपूर्ण है।
- USTR ने डिजिटल सर्विस टैक्स के संबंध में जांच रिपोर्ट को रिलीज करते हुए कहा कि हम अभी कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सभी उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन जारी रखेंगे।
- USTR की ओर से यूएस ट्रेड अधिनियम, 1974 के सेक्शन 301 के तहत कई सेक्टर्स में जांच जारी है। इसके आधार पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस छोड़ने से पहले टैरिफ लगा सकते हैं। इसके बीच फ्रांस के डिजिटल सर्विसेज टैक्स को लेकर एडवांस जांच चल रही है।
- USTR ने डिजिटल टैक्स के विरोध में फ्रांस से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया है। इसके लिए विभाग द्वारा 6 जनवरी की डेडलाइन तय की गई थी।

3. 2% इक्वेलाइजेशन लेवी वसूलता है भारत

- भारत 1 अप्रैल, 2020 के इक्वेलाइजेशन लेवी वसूल रहा है। इसे गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है।
- इससे पहले सरकार ने डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनियों पर 6% लेवी लगाई थी। विदेश में स्थित डिजिटल कंपनियों के भारतीय कारोबार पर यह लेवी लगाई गई थी।
- USTR ने जांच के दौरान 5 नवंबर, 2020 को भारत से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा था।
- USTR ने जांच में पाया है कि भारत यह डिजिटल सर्विसेज टैक्स केवल नॉन रेजीडेंट कंपनियों से वसूलता है।
- यूएसटीआर द्वारा अमेरिकी सरकार के यूएस ट्रेड अधिनियम, 1974 के तहत कार्यवाई की जाती है।
- इस अधिनियम के तहत यूएसटीआर जाँच करती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी भेदभाव-पूर्ण नीतियाँ तो नहीं अपनायी जा रही हैं जो अमेरिका के हितों के विपरीत हों।
- यूएसटीआर अपनी जाँच में भेदभावपूर्ण नीतियों को पाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को इस संबंध में टैरिफ या अन्य प्रतिबंध लगाने की सलाह देता है।

4. यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव-यूएसटीआर

- यूनाइटेड स्ट्रेट ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (यूएसटीआर), अमेरिकी सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास व समन्वयन संबंधी निर्णयश लेती है।

05 भारत में बर्ड फ्लू

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में कोरोना महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस को लेकर चेतावनी जारी की गयी है।

2. विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले

- मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ केरल में पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों पक्षियों के मौत के मामले सामने आये हैं।
- हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित अंतरराष्ट्रीय रामसर वेटलैंड पौंग बांध में कई विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत होने पर भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान ने इसकी सैंपल की जांच की।
- राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान द्वारा अपने जांच के निष्कर्षों में बर्ड फ्लू वायरस H5N1 के होने की पुष्टि की गयी है।
- राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में कई कौओं की मौत होने पर इसकी जांच हेतु सैंपल भेजें जाने पर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान द्वारा बर्ड फ्लू की पुष्टि की गयी है।
- केरल में अलापुझा और कोट्टायम जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है।
- इसके साथ ही गुजरात के जूनागढ़ में बतख-टिटहरी-बगुला समेत 53 पक्षियों की मौत में भी बर्ड फ्लू की आशंका व्यक्त की गयी है।

3. क्या है बर्ड फ्लू?

- एवियन एन्फ्लूएंजा को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, ये खतरनाक वायरल संक्रमण इंसानों और पक्षियों को अधिक प्रभावित करता है।
- एवियन एन्फ्लुएंजा पहली बार 1997 में हांगकांग से रिपोर्ट किया गया था।
- यह वायरस खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले पक्षियों जैसे मुर्गियों, टर्की, बटेर, गिनी फाउल, आदि सहित पालतू और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है।
- सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला बर्ड फ्लू वायरस H5N1 है जिससे इंसान और पक्षियों की मौत भी सकती है। H5N1 वायरस मुर्गी पालन के लिये विशेष रूप से घातक साबित होता है।
- सामान्यत: यह वायरस पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन यह मानव सहित अन्य स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित मुर्गियों या अन्य संक्रमित पक्षीयों के संपर्क में आता है तो वह भी इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है।

4. बर्ड फ्लू के लक्षण

- बर्ड फ्लू के लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं लेकिन सांस लेने में अधिक समस्या और उल्टी होने का एहसास इसका विशेष लक्षण हैं। इसके कुछ सामान्य लक्षण निम्नवत हैं-
- बुखार और सिर में दर्द रहना
- हमेशा कफ रहना और नाक बहना
- गले में सूजन और मांसपेशियों में दर्द
- दस्त और उल्टी होना
- सांस लेने में समस्या, तथा निमोनिया के लक्षण परिलक्षित होते हैं।
- आंख में कंजंक्टिवाइटिस।

5. बर्ड फ्लू का उपचार

- संक्रमित पक्षियों विशेषकर संक्रमण से मारे पक्षियों से दूरी बनाकर रहना।
- बर्ड फ्लू का संक्रमण अगर फैला है तो पक्षियों के मांस का खाद्य के रूप में प्रयोग करने से बचे।
- बर्ड फ्लू के इलाज के लिए एंटीवायरल दावा ओसेल्टामिविर, टैमीफ्लू और जानामिविर का प्रयोग किया है।

06 भारत में अनुदैर्ध्य एजिंग का अध्ययन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा भारत के अनुदैर्ध्य एजिंग अध्ययन (LASI) वेव -1 रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया।

2. परिचय

- एलएएसआई भारत में उम्रदराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वे है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस अध्ययन में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS), मुंबई के हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग आदि के सहयोग से भारत के अनुदैर्ध्य एजिंग का अध्ययन किया है।
- यह भारत का पहला तथा विश्व का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है जो सामाजिक, स्वास्थ्य तथा आर्थिक खुशहाली के पैमानों पर वृद्ध आबादी के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से लॉगिट्यूडिनल डाटाबेस प्रदान करता है।

3. कार्यप्रणाली

- इसके अंतर्गत वेव-1 में 45 वर्ष तथा उससे ऊपर के 72,250 व्यक्तियों और उनके जीवनसाथी का बेसलाइन सैम्पल कवर किया गया है।
- इसके अलावा इसमें 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के 31,464 व्यक्ति तथा 75 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के 6,749 व्यक्ति शामिल हैं। ये सैम्पल सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए।

4. सर्वे का लाभ

- एलएएसआई से प्राप्त साक्ष्य का उपयोग वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को मजबूत और व्यापक बनाने में किया जाएगा और इससे वृद्धजनों की आबादी के लिए प्रतिरोधी तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने में मदद मिलेगी।
- क्योंकि 2011 की जनगणना में वृद्धजनों की 60 वर्ष से अधिक की आबादी भारत की आबादी का 8.6 प्रतिशत थी यानी 103 मिलियन वृद्ध लोग थे। साथ ही तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धिदर से 2050 में वृद्धिजनों की आबादी बढ़कर 319 मिलियन हो जाएगी।
- यह रिपोर्ट वृद्धजन आबादी के लिए राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय कार्यक्रमों और नीतियों के लिए आधार प्रदान करेगी। इस रिपोर्ट का महत्व दुनिया भर में बढ़ती जीवन प्रत्याशा से उपजा है।
- एलएएसआई के निष्कर्षों का उपयोग बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के दायरे को और अधिक मजबूत व विस्तार करने, बुजुर्गों और सबसे कमजोर बुजुर्ग आबादी के लिए रोकथाम और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए किया जाएगा।

07 वैश्विक जलवायु स्थिति पर अनंतिम रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की हालिया वैश्विक जलवायु स्थिति अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 अब तक के तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है। इसके अलावा 2011-2020 का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक होगा।
- ध्यातव्य है कि यह केवल अनंतिम रिपोर्ट (Provisional Report) है और अंतिम रिपोर्ट (Final Report) मार्च 2021 में प्रस्तुत की जाएगी।

2. वैश्विक तापमान में वृद्धि

- 'स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2020' पर डब्ल्यूएमओ की अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक महासागरों का गर्म होना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और वर्ष 2020 में वैश्विक महासागरों का 80% से ज्यादा हिस्सा कुछ समय के लिए समुद्री ग्रीष्म लहर की चपेट में रहा।
- रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद ग्रीन हाउस गैसों के वातावरणीय संकेंद्रण के स्तरों का बढ़ना जारी है।
- रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर (2020) की अवधि में वैश्विक औसत सतह तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर (1850-1900) से 1.2°c से अधिक हो सकता है।

3. अत्यधिक प्रभाव डालने वाली परिघटनाएं

- पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, चीन और वियतनाम में करोड़ों लोग विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अफ्रीका में सूडान और केन्या पर सबसे बुरा असर पड़ा है। केन्या में जहां 285 लोगों की मौत हुई है वही सूडान में 155 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
- दक्षिण एशियाई देशों में से भारत में 1994 से अब तक दूसरी बार मॉनसून में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। पाकिस्तान में अगस्त सबसे ज्यादा वर्षा वाला महीना रहा। बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार समेत संपूर्ण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ की घटनाएं हुई।
- चीन में यांग्त्जे नदी के जल भरण क्षेत्रों में लगातार भारी वर्षा हुई जिसकी वजह से जबरदस्त बाढ़ आई। इस आपदा की वजह से 15 अरब डालर से ज्यादा का नुकसान हुआ और 279 लोगों की मौत हुई।
- वियतनाम में उत्तर-पूर्वी मानसून की आमद के साथ हुई भारी बारिश में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान और विक्षोभ की वजह से और बढ़ोत्तरी हो गई। इस कारण पांच हफ्तों से भी कम समय में भूस्खलन की आठ घटनाएं हुई।

4. विश्व मौसम विज्ञान संगठन

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन(डबल्यूएमओ), एक अंतरसरकारी संगठन है।
- डब्ल्यूएमओ कन्वेंशन के अनुमोदन से मार्च 23, 1950 को स्थापित डब्लूएमओ, एक साल बाद मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), जल विज्ञान और भू-भौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गया।
- यह संगठन, पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध और मौसम के बारे में जानकारी देता है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन(डबल्यूएमओ) का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

5. निष्कर्ष

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई मौजूदा वैश्विक मंदी की वजह से प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में कमी लाने की नीतियों को लागू करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- इसके लिए प्रदूषण मुक्त और सतत सार्वजनिक मूलभूत ढांचे में निवेश को बढ़ाना होगा। इससे क्षतिपूर्ति के दौर में भी जीडीपी और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अनुसार पशुओं के प्रति क्रूरता करने वालों को दंडित किया जा सकता है।
2. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या : पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अनुसार पशुओं के प्रति क्रूरता करने वालों को दंडित किया जा सकता है। विदित हो कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 (न कि 1972) में की गई थी। इस तरह कथन 1 सही है, अतः उत्तर (a) होगा।

02 भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी

प्र. भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कोवैक्स एंड गावी के नेतृत्व वाले समूह में अमेरिका सहित 189 देश शामिल हैं।
2. इस समूह का उद्देश्य वर्ष 2021 के अंत तक 2 बिलियन खुराकों की खरीद करना है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या : कोवैक्स एंड गावी के नेतृत्व वाले समूह में अमेरिका शामिल नहीं है। भारत सहित 189 देश इस समूह के सदस्य हैं। विदित हो कि इस समूह का उद्देश्य वर्ष 2021 के अंत तक 2 बिलियन खुराकों की खरदी करना है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

03 राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2020

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस नीति का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रित एक बेहतर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके लघु, मध्यम और दीर्घकालिक मिशन मोड वाली परियोजनाओं के माध्यम से बड़ा बदलाव लाना है।
2. इस नीति के अनुसार समलैंगिक, ट्रांसजेन्डर समुदाय आदि को भी लैंगिक समता संवाद में शामिल किया जाएगा।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या : राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2020 का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रित एक बेहतर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके लघु, मध्यम और दीर्घकालिक मिशन मोड वाली परियोजनाओं के माध्यम से बड़ा बदलाव लाया है। इस नीति के अनुसार समलैंगिक, ट्रांसजेन्डर समुदाय आदि को भी लैंगिक समता संवाद में शामिल किया जाएगा। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (d) होगा।

04 यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव की रिपोर्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव, इजरायल सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है।
2. यूएसटीआर ने डिजिटल टैक्स के विरोध में फ्रांस से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है।
3. यूएसटीआर द्वारा अमेरिकी सरकार के यूएस ट्रेड अधिनियम, 1974 के तहत कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या : यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव अमेरिकी सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यूएसटीआर ने डिजिटल टैक्स के विरोध में फ्रांस से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया है। विदित हो कि यूएसटीआर द्वारा अमेरिकी सरकार के यूएस ट्रेड अधिनियम, 1974 के तहत कार्यवाही की जाती है। इस तरह कथन 1 और 2 गलत है, अतः उत्तर (c) होगा।

05 भारत में बर्ड फ्लू

प्र. भारत में बर्ड फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एवियन एन्फ्लूएंजा का पहला मामला वर्ष 1997 में हांगकांग में पाया गया था।
2. यह वायरस मुर्गियों, टर्की, बटेर मिनी फाउल सहित अनेक प्रजातियों को प्रभावित करता है।
3. एवियन एन्फ्लूएंजा को सामान्यतः बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1,2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में कोरोना महामारी के बीच राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखण्ड और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस को लेकर चेतावनी जारी की गयी है। बर्ड फ्लू के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (d) होगा।

06 भारत में अनुदैर्ध्य एजिंग का अध्ययन

प्र. भारत में अनुदैर्ध्य एजिंग का अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एलएसएसआई भारत में उम्रदराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जाँच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वे है।
2. यह भारत का पहला तथा विश्व का सबसे बड़ा सर्वे है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) दोनों में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या : हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ॰ हर्षवर्धन द्वारा भारत के अनुदैर्ध्य एजिंग अध्ययन (LASI) वेव-1 रिपोर्ट-2020 को जारी किया गया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

07 वैश्विक जलवायु स्थिति पर अनंतिम रिपोर्ट

प्र. वैश्विक जलवायु स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

1. रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के बाद भी ग्रीन हाउस गैसों के वातावरणीय संकेंद्रण के स्तरों का बढ़ना जारी है।
2. रिपोर्ट के मुताबिक महासागरों का गर्म होना रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है।
3. वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 2024 तक अस्थायी रूप से वैश्विक तापमान 1.5°c से अधिक हो सकता है।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया वैश्विक जलवायु स्थिति अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 अब तक के तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है। साथ ही साथ 2011-2020 का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक होगा। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (d) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 भारतीय अर्थव्यवस्था में V–आकार का सुधार

चर्चा में क्यों

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचेम) के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021 में तेजी से सुधार देखा जा रहा है और अर्थव्यवस्था V-आकार के सुधार की ओर तेजी से बढ़ रही है।

V-आकार का सुधार (V-shaped recovery)

- अर्थव्यवस्था में वी-आकार का सुधार, एक प्रकार की आर्थिक मंदी के बाद उसकी रिकवरी है जो ग्राफ में "oh" आकार में प्रदर्शित होता है।
- V-आकार की वृद्धि में किसी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद तेजी से सुधार होता है।

V-आकार के सुधार की विशेषताएँ

- अर्थव्यवस्था में V-आकार का सुधार तेज आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन के उपायों में त्वरित और निरंतर सुधार को दर्शाता है।
- यह बहुत छोटे समय में आर्थिक क्रियाओं में तीव्र गिरावट को दिखाता है।
- लगातार गिरावट के दौरान किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के चलते होने वाले तीव्र सुधार के प्रदर्शन को V-आकार के ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया था।
- वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था मे होने वाले तीव्र गिरावट के बाद अब जिस तेजी से आर्थिक क्रियाकलाप में सुधार हो रहा है उससे भारत की अर्थव्यवस्था में V-आकार का सुधार देखने को मिल रहा है।

- इससे पहले 2008 की मंदी के दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था में V-आकार का सुधार हुआ था।

वर्तमान में V-आकार के सुधार के कारण

- कोरोना वायरस की शुरुआत से पहले भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद तक सुस्त हो चुकी थी और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को और कमजोर कर दिया था।
- नवंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2020-21 के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था V-आकार की वृद्धि से प्रदर्शित कर सकती है जिसका कारण अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती और लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाना है।
- इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत मिशन की वजह से भी अर्थव्यवस्था पुनरोद्धार की राह आसान हुई है।
- साथ ही अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक कृषि क्षेत्र से समर्थन मिल रहा है क्योंकि यह क्षेत्र विनिर्मान और सेवा क्षेत्र की तुलना में न के बराबर प्रभावित हुआ है।
- लॉकडाउन हटाये जाने के बाद से निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं।
- आर्थिक गतिविधियों में तेज सुधार की वजह माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत दिसंबर महीने में अब तक का रिकार्ड 1.15 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है, जो उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

आर्थिक मंदी में सुधार के अन्य प्रमुख प्रारूप

- **जेड-आकार की रिकवरी (Z-shaped recovery):** यह सबसे आशावादी परिदृश्य होता है, इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तेजी से वृद्धि देखी जाती है। Z-प्रकार का चार्ट दर्शाता है कि हालात के सामान्य होने से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है (जैसे, लॉकडाउन हटाए जाने के बाद खरीददारी में वृद्धि इत्यादि)।
- **U- आकार की रिकवरी (U-shaped recovery):** U-आकार की बहाली में ऐसा परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम विकास दर के बाद भी यह धीरे-धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। इस प्रवृत्ति में लोगों की नौकरियों के ऊपर असर पड़ता है और लोगों की बचत में कमी देखने को मिलता है।
- **W-आकार की रिकवरी (W-shaped recovery)** W-आकार की रिकवरी वाली प्रवृत्ति जोखिम युक्त होती है। इसमें विकास दर में कमी तथा वृद्धि होती है, तथा उभरने के बाद यह फिर गिरती है और पुनः वृद्धि करती है, इस प्रकार, इसमें डब्ल्यू-आकार का चार्ट बनता है। जानकारों का मानना है कि अगर कोरोना महामारी की दूसरी लहर आती है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।
- **L-आकार की रिकवरी (L-shaped recovery):** यह अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद विकास निम्न स्तर पर पहुँच जाता है और यह लंबे समय तक ठीक नहीं हो पता है। इसमें, अर्थव्यवस्था वर्षों के बाद भी वर्तमान जीडीपी के स्तर को हासिल करने में विफल रहती है। L-आकार से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में स्थायी नुकसान होता है।

02 नेप्च्यून बॉल्स

चर्चा में क्यों

- हाल ही में एक शोध में पाया गया है कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद समुद्री घास प्लास्टिक प्रदूषण को प्राकृतिक रूप से फाइबर बंडलों में बदल रही है।
- समुद्री घास द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाए गए इन फाइबर बंडलों को 'नेप्च्यून बॉल्स' के नाम से जाना जाता है।

शोध अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- यह शोध बार्सिलोना विश्वविद्यालय में जीवविज्ञानियों द्वारा भूमध्यसागर के क्षेत्र में किया गया है।
- साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया है कि इंसानों की मदद के बिना ही हर साल अकेले भूमध्यसागर में लगभग 900मिलियन प्लास्टिक की वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है।
- प्लास्टिक का यह मलबा समुद्री घास के अवशेषों में फंसकर समुद्रतट में पहुंचता है।
- समुद्री घास प्राकृतिक रूप से प्लास्टिक मलबे को समुद्र से बाहर निकाल कर समुद्री की स्वच्छता को बनाये रखती है।

समुद्री घास

- समुद्री घास समुद्र तथा महासागरों में पानी के अंदर पाई जाने वाली घास है। समुद्री घास फूल वाले समुद्री पौधे होते हैं, जो सागरीय परिस्थितिकी के प्रति अनुकूलित होते हैं।
- समुद्री घास समान्यतः उथले समुद्री तटों में पाई जाती हैं और कई बार यह व्यापक घने घास के मैदान का भी निर्माण करती हैं।
- पूरे विश्व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों में लगभग 72 प्रकार की समुद्री घास प्रजातियां पायी जाती हैं।

समुद्री घास के लाभ

- समुद्री घास महासागर पारिस्थितिक तंत्रों और तटीय क्षेत्रों में रहने वालों मनुष्यों के लिए अत्यधिक महत्व रखती है।
- समुद्री घास पानी की गुणवत्ता में सुधार करने, CO_2 को अवशोषित और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- इसके अलावा मछलियों की सैकड़ों प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास और शरणस्थली प्रदान करती है।
- समुद्री घास तटीय खाद्य जाल के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है।
- चूंकि यह घास समान्यतः तटीय क्षेत्रों में पायी जाती है, जिससे यह समुद्र तट के क्षरण को रोकने में और विनाशकारी तूफान के प्रभाव को कम करने में मदद करती है।

03 रिसाइक्लिंग योग्य व गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा

चर्चा में क्यों

- हाल ही में केरल में रिसाइक्लिंग योग्य व गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे (recyclable and non & biodegradable waste) के लिए आधार मूल्य तय किया गया है।

प्रमुख बिन्दु

- हाल ही में केरल में स्थानीय सरकार के तहत गठित 'क्लीन केरल कंपनी लिमिटेड' (Clean Kerala Company Limited-CKCL) ने रिसाइक्लिंग योग्य व गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए आधार मूल्य तय किया गया है। यह देश की किसी कंपनी द्वारा इस तरह का प्रथम प्रयास है।
- क्लीन केरल कंपनी लिमिटेड (CKCL) के इस कदम को हरिथा कर्म सेना (Haritha Karma Sena-HKS) के स्वयंसेवकों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हरिथा कर्म सेना के स्वयंसेवकों को ग्रीन आर्मी के रूप में भी जाना जाता है।
- यह ग्रीन आर्मी पूरे केरल के घरों और कार्यालयों से बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल दोनों ही प्रकार के अपशिष्ट का एकत्रण करती है।
- क्लीन केरल कंपनी लिमिटेड ने न्यूजपेपर, प्लास्टिक की शराब की बोतलें, दूध के पैकेट, कांच की बोतलें, एल्युमीनियम के डिब्बे और कार्डबोर्ड सहित रिसाइकल व नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे के 20 वेरिएंट के लिए बेल्ड और अनबेल्ड (baled and unbaled) दोनों दरों की घोषणा की है।
- केरल एक दिन में लगभग 1808 टन गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे (non-biodegradable waste) का उत्पादन करता है, जिनमें से प्लास्टिक 400 टन से अधिक है।

अपशिष्ट (Waste)

- अपशिष्ट (Waste) से तात्पर्य अनुपयोगी या अवांछनीय सामग्री से है। दरअसल मानव के दैनिक कार्यों के पश्चात जो भी पदार्थ

अनुपयोगी या अवांछनीय सामग्री के रूप में बच जाता है, उसे ही अपशिष्ट (Waste) कहते हैं।

- अवस्था के अनुसार , अपशिष्ट (Waste) तीन प्रकार के होते हैं- ठोस अपशिष्ट (Solid Waste), तरल अपशिष्ट (Wet Waste) और गैसीय अपशिष्ट। हालाँकि ठोस व तरल अपशिष्ट गैसीय की अपेक्षा अधिक उत्पन्न किया जाता है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में कचरे के ढेर आज एक आम बात बन गई है, जो पर्यावरण, नदी, तलाब और कुँओं तथा झीलों को प्रदूषित कर रहे हैं।
- लगातार बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण की तेज गति की वजह से देश को अपशिष्ट प्रबंधन की एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- अपशिष्ट या कचरे का आयतन 62 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 2030 तक लगभग 150 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से भारत में प्रतिदिन कचरा उत्पन्न हो रहा है, इससे आगे चलकर भारी मात्रा में प्रति वर्ष लैंडफिल क्षेत्र की जरुरत होगी। इसके अतिरिक्त, यहाँ उचित वैज्ञानिक उपचार के बिना कचरे का अंधाधुंध निपटान भी हो रहा है।

अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ

- प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा: वनों, गैसों और पानी जैसे कई प्राकृतिक संसाधनों की घटती समस्या हमारे लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बन गई है। इसलिए आवश्यक है कि प्लास्टिक आदि की बनी वस्तुओं के पुन: उपयोग से हम वनों की कटाई इत्यादि को रोक सकते हैं।
- ऊर्जा क्षमता में बढ़ोत्तरी: पुनरावृत्ति ऊर्जा का उत्पादन करने का एक शानदार तरीका है। नई वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रयोगों से यह पता चला है कि हमारे घरों के अपशिष्ट पदार्थों को एक विशेष प्रणाली के द्वारा बिजली उत्पन्न में प्रयोग किया जा सकता है।

04 समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल

चर्चा में क्यों

- भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल-21 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया।

सी विजिल (SEA VIGIL)

- सी वीजिल हर दूसरे साल आयोजित किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है।
- इस अभ्यास में देश के समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद 13 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदाय भी शामिल होते हैं।
- समुद्री रक्षा अभ्यास सी-विजिल-21 के दूसरे संस्करण का आयोजन 12-13 जनवरी 2021 को किया गया। समुद्री रक्षा अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में हुआ था।
- बड़े भौगोलिक क्षेत्र, संबंधित लोगों की संख्या और अभ्यास में शामिल होने वाले भागीदारों की संख्या को देखते हुए इस अभ्यास का दायरा काफी बड़ा है।

ऐसे समुद्री रक्षा अभ्यास की उपयोगिता

- मुंबई में 26 नवंबर में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत के पूरे समुद्र तटीय क्षेत्र की सुरक्षा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि मुंबई में यह आतंकी हमला समुद्र के रास्ते से ही हुआ था।
- यह अभ्यास भारतीय नौसेना के थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपेक्स (Theatre-level Readiness Operational Exercise- TROPEX)की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
- सी विजिल और ट्रोपेक्स अभ्यास मिलकर समुद्री इलाकों की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।
- 'सी विजिल-21' समुद्री इलाकों में सुरक्षा की स्थिति का वास्तविक आकलन करने के साथ आगे उसमें सुधार की संभावनाओं का अवसर देता है, जिससे हमारी समुद्री सुरक्षा और मजबूत हो सके।
- सी विजिल अभ्यास के अलावा छोटे पैमाने पर समुद्री इलाकों के राज्यों में नौसैनिक अभ्यास भी किए जाते हैं, जिसमें एक से ज्यादा राज्य मिलकर भी अभ्यास करते हैं। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करना है। यह अभ्यास उच्च स्तर पर समुद्री क्षेत्र में भारत की सुरक्षा तैयारियों का भी आकलन करने में मदद करता है।

05 स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो तकनीकी का महत्व

चर्चा में क्यों

- जर्मनी स्थिति बॉन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान दल ने कोविड-19 का कारण बनने वाले SARS-CoV-2 वायरस से लड़ने में सक्षम एक नैनो आकार के एंटीबॉडी की पहचान की है।
- ये नैनोबॉडी क्लासिक एंटीबॉडी की तुलना में बहुत छोटे हैं और वे क्षतिग्रस्त ऊतकों तक आसानी से पहुँच जाते हैं और इन्हें बड़ी मात्रा में उत्पादित भी किया जा सकता है।

क्या है नैनोबॉडी?

- एक एकल-डोमेन एंटीबॉडी (single-domain antibody-sdAb) को ही नैनोबॉडी के नाम से भी जाना जाता है।
- नैनोबॉडी एंटीबॉडी का एक ऐसा एकल खंड होता है जो मोनोमेरिक वैरिएबल एंटीबॉडी डोमेन युक्त होता है।
- यह एक एंटीबॉडी की तरह ही किसी विशिष्ट एंटीजन के विरुद्ध चुनिंदा रूप से कार्य करने में सक्षम होता है।
- एकल-डोमेन एंटीबॉडी सामान्य एंटीबॉडी से आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका आकार केवल 12-15 kDa के आणविक भार के बराबर होता है।

नैनो तकनीक का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग

- चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो तकनीकी का सर्वाधिक महत्व है। कोशिकीय संरचना और कोशिकीय जैव रासायनिक अभिक्रियाएं नैनो पैमाने के अंतर्गत ही आती हैं और इस पैमाने पर पहुँचकर अध्ययन करना जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन करना नैनो तकनीक के द्वारा संभव हुआ। नैनो तकनीकी का इस्तेमाल निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रो में किया जा सकता है-
- **अति संवेदनशील रोग सूचक (Highly Sensitive Disease Detectors):** इसके अंतर्गत ऐसे नैनो संवेदकों का निर्माण किया जाता है जो किसी रोग के कारण पैदा होने वाले रसायन या प्रोटीन के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह नैनो संरचना शरीर के अंदर रोग पैदा करने वाले कारकों से जुड़कर रोग होने की पुष्टि करता है। इसकी सहायता से कैंसर,

अल्जाइमर, एचआईवी संक्रमण आदि का पता प्रारंभिक अवस्था में ही लगाया जा सकता है।

- **लक्षित रूप से दवा पहुँचाने की विधि (Targeted Drug Delivery System):** नैनो संवेदकों के साथ कैंसर कोशिकाओं तथा रोगाणुओं को मारने के लिए दवाओं को भी समायोजित किया जा सकता है। इस प्रणाली के उपयोग से बीमार कोशिकाओं और रोगाणुओं को पहचान कर नष्ट किया जा सकता है। इस पद्धति के उपयोग से उपचार की सटीकता बढ़ेगी और दवाओं का कुप्रभाव शरीर के अन्य अंगों और ऊतकों पर नहीं होगा।
- ग्लासगो विश्वविद्यालय (UK) के वैज्ञानिकों ने मेनिंजाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) की जाँच के लिए चाँदी नैनो कण एवं लेजर आधारित एक जाँच प्रक्रिया का आयोजन किया है।
- डीआरडीओ तथा आईआईएससी के सम्मिलित प्रयास से नैनो संवेदकों पर आधारित टाइफाइड जाँच किट का विकास किया गया है।

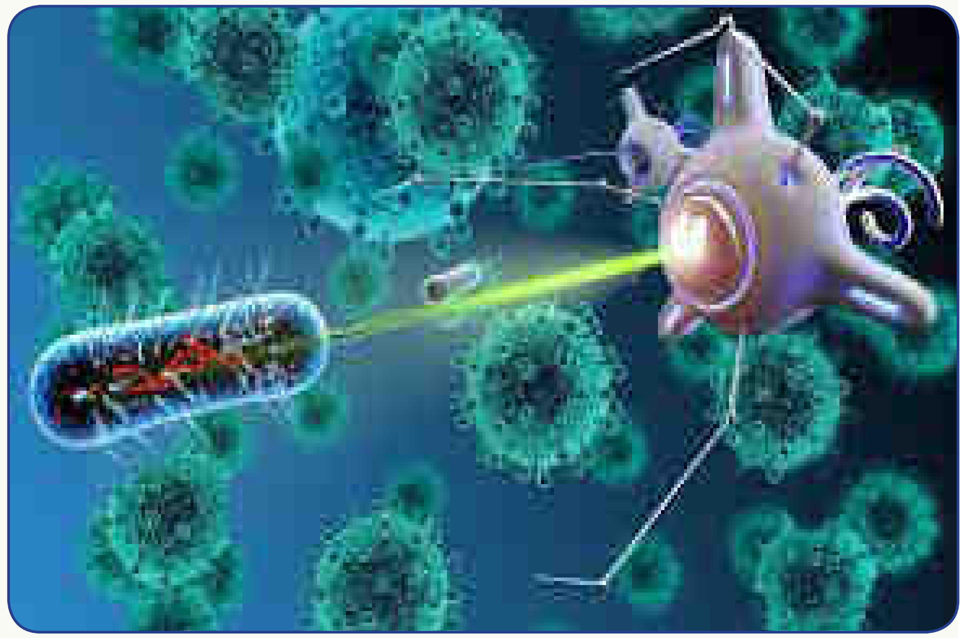

- कार्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रक्त में उपस्थित कैंसर कोशिकाओं के नष्ट करने वाली नैनो मशीन का विकास किया है।
- **ऊतक अभियांत्रिकी (Tissue Engineering):** शिकागो स्थित Feinberg School of Medicine के शोधकर्त्ताओं ने नैनो पदार्थ युक्त एक जेल का विकास किया है जो क्षतिग्रस्त ऊतकों में कोशिकीय विभाजन की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है जिससे घाव तेजी से भरते हैं।

06 जल्लीकट्टू

चर्चा में क्यों

- पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोगों के पशु अधिकार संगठन पेटा ने तमिलनाडू सरकार से जल्लीकट्टू खेल को आयोजित करने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है।
- पेटा ने यह आग्रह 50 से अधिक डॉक्टरों के हस्ताक्षर युक्त पत्र के आधार पर किया है, जिसमे कहा गया है कि खेल एक गैर-आवश्यक गतिविधि है और इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा है।

जल्लीकट्टू के बारे में

- जल्लीकट्टू पोंगल के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक परंपरागत खेल है जिसमें बैलों को इंसानों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।
- जल्लीकट्टू तमिल शास्त्रीय युग (400-100 ईसा पूर्व) से संबंधित एक प्राचीन खेल है। इसका वर्णन प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शीलपादिकारम और दो अन्य ग्रन्थों

मालीपादुकादम और कालीथोगई में भी मिलता है। इसके अलावा, एक 2500 साल पुरानी गुफा पेंटिंग में एक बैल को नियंत्रित करने वाले एक आदमी को दर्शाया गया है जिसे इसी खेल से जोड़ा जाता है।
- जल्लीकट्टू को येरुथा जुवुथल,मदु पिदिथल, पोलरुधु पिदिथल जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है।

जल्लीकट्टू से जुड़ा विवाद

- 2010 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुई एक जाँच में कहा गया कि जल्लीकट्टू स्वाभाविक रूप से जानवरों के लिए क्रूर है। इसके बाद से भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के संघ (FIAPO) और पेटा इंडिया जैसे पशु कल्याण संगठनों ने इस प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया है।
- वर्ष 2014 में पेटा की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित कर दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राज्य भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुये।
- इसके बाद 2017 में तमिलनाडू सरकार ने सर्वसम्मति से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बैल की देशी नस्लों के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया और इसके बाद जल्लीकट्टू आयोजन पर प्रतिबंध भी समाप्त हो गया।

07 जावा सागर

चर्चा में क्यों

- हाल ही में इंडोनेशिया की श्रीविजया एयरलाइन का एक विमान बोइंग 737-500 जावा सागर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इंडोनेशिया की नौसेना ने इस विमान के ब्लैक बॉक्स को जावा सागर से खोज लिया है।

जावा सागर

- जावा सागर पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया के जावा द्वीप के ठीक उत्तर में स्थित एक सागर है।
- इसके उत्तर में दक्षिण चीन सागर और पूर्व में फ्लोरस सागर स्थित है।
- कम औसत गहराई वाले इस सागर का क्षेत्रफल लगभग 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है।
- मत्स्य आखेट जावा सागर में होने वाली प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। क्षेत्र में समुद्री जीवों की 3,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। करीमुंजवा राष्ट्रीय उद्यान जावा सागर के क्षेत्र में ही स्थित है।

क्या होता है ब्लैक बॉक्स?

- 'ब्लैक बॉक्स' किसी भी विमान का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। यह वायुयान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है।
- ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी कहा जाता है। इसे यात्री, कार्गो और फाइटर सभी प्रकार के विमानों में लगाया जाता है।
- ब्लैक बॉक्स बहुत ही मजबूत मानी जाने वाली धातु टाइटेनियम का बना होता है और टाइटेनियम के ही बने बॉक्स में बंद होता है ताकि ऊंचाई से जमीन पर गिरने या समुद्री पानी में गिरने की स्थिति में भी इसको कम से कम नुकसान हो।

'ब्लैक बॉक्स' समान्यतः दो प्रकार के बॉक्स होते हैं

- **फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर:** इसमें विमान की दिशा, ऊँचाई (altitude), ईंधन, गति, हलचल (turbulence), केबिन का तापमान सहित 88 प्रकार के आंकड़ों की 25 घंटों से अधिक की रिकार्डिंग को सुरक्षित रखा जा सकता है।
- यह बॉक्स 11000°C के तापमान में भी लगभग एक घंटे तक सुरक्षित रह सकता है जबकि 260°C के तापमान में 10 घंटे से अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है।
- **कॉकपिट वोइस रिकॉर्डर:** यह बॉक्स विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले के 2 घंटों के दौरान विमान के अंदर की आवाजों को रिकॉर्ड करता है
- इसमें विमान के इंजन की आवाज, आपातकालीन अलार्म की आवाज, केबिन और कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुर्घटना से पहले विमान की स्थिति क्या थी और दुर्घटना का कारण क्या है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, भारत में कौशल विकास को किस प्रकार समृद्ध करेगा? चर्चा करें।

02 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 पशुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में किस प्रकार सहायक है? उल्लेख करें।

03 अमेरिकी प्रशासन का यह कहना है कि एक सशक्त भारत का निर्माण चीन के प्रति-संतुलन के लिए अति आवश्यक है। इससे आप कितना सहमत हैं? टिप्पणी करें।

04 हाल ही में भारत और जापान ने आईसीटी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के संदर्भ में भारत-जापान संबंधों पर विस्तार से चर्चा करें।

05 वर्तमान समय में भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में कमी आई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। क्या यह भारत के विकसित होने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

06 कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है फिर भी किसानों की स्थिति दयनीय और विचारणीय है। इसके कारणों पर उदाहरण के साथ प्रकाश डालें।

07 वैश्विक जलवायु स्थिति पर आई रिपोर्ट के अनुसार महासागर तेजी से गर्म होते जा रहे हैं। इससे पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 हाल ही में चर्चित 'सरुवानी पहाड़ियाँ' किस राज्य में स्थित हैं?

तमिलनाडु

02 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है?

85वां

03 संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को 'आतंकवाद प्रायोजक राज्य' के रूप में नामित किया है?

क्यूबा

04 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा देश बना है?

एंडोरा

05 भारत किस राज्य में वैनेडियम पाये जाने की संभावना व्यक्त की गयी है?

अरुणाचल प्रदेश

06 भारत के किस राज्य ने 'फायर पार्क' का उद्घाटन किया है?

ओडिशा

07 हाल ही में किस एशियाई देश ने मृत्युदंड को समाप्त किया है?

कजाकिस्तान

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

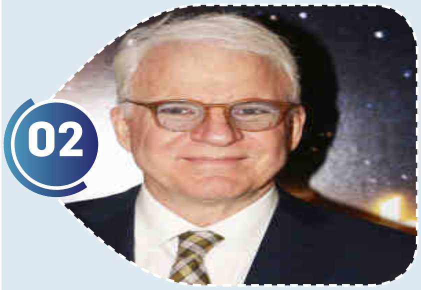

01 न तो भविष्य का डर होना चाहिए न अतीत के लिए कभी रोना चाहिए। न तो भविष्य का डर होना चाहिए न अतीत के लिए कभी रोना चाहिए।

पी.बी. रोली

02 इतने अच्छे बनें कि आपकी उपेक्षा करने का किसी में साहस ही न हो।

स्टीव मार्टिन

03 खुश वो नहीं, जिसके पास हर चीज सबसे बेहतर है, खुश वो है जो अपने पास की हर चीज को बेहतर मानता है।

डेनियल ऑर्नर

04 विश्वास और प्रार्थना आत्मा के दो विटामिन हैं, कोई भी व्यक्ति इनके बिना स्वस्थ नहीं रह सकता है।

महालिया जैकसन

05 शेष ऋण, शेष अग्नि और शेष रोग पुनः पुनः बढ़ते हैं, अतः इन्हें शेष कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

शौनकीय नीतिसार

06 प्राथमिकताएँ तय करें और उन कामों को ना कहना सीखें जो आपका समय खर्च करते हैं।

बारेन बफे

07 जो चाहते हैं उस पर ध्यान केन्द्रित करें, उस दिशा में कदम बढ़ाएँ और सफल हो जाएँ।

जॉर्ज कोलराइजर

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

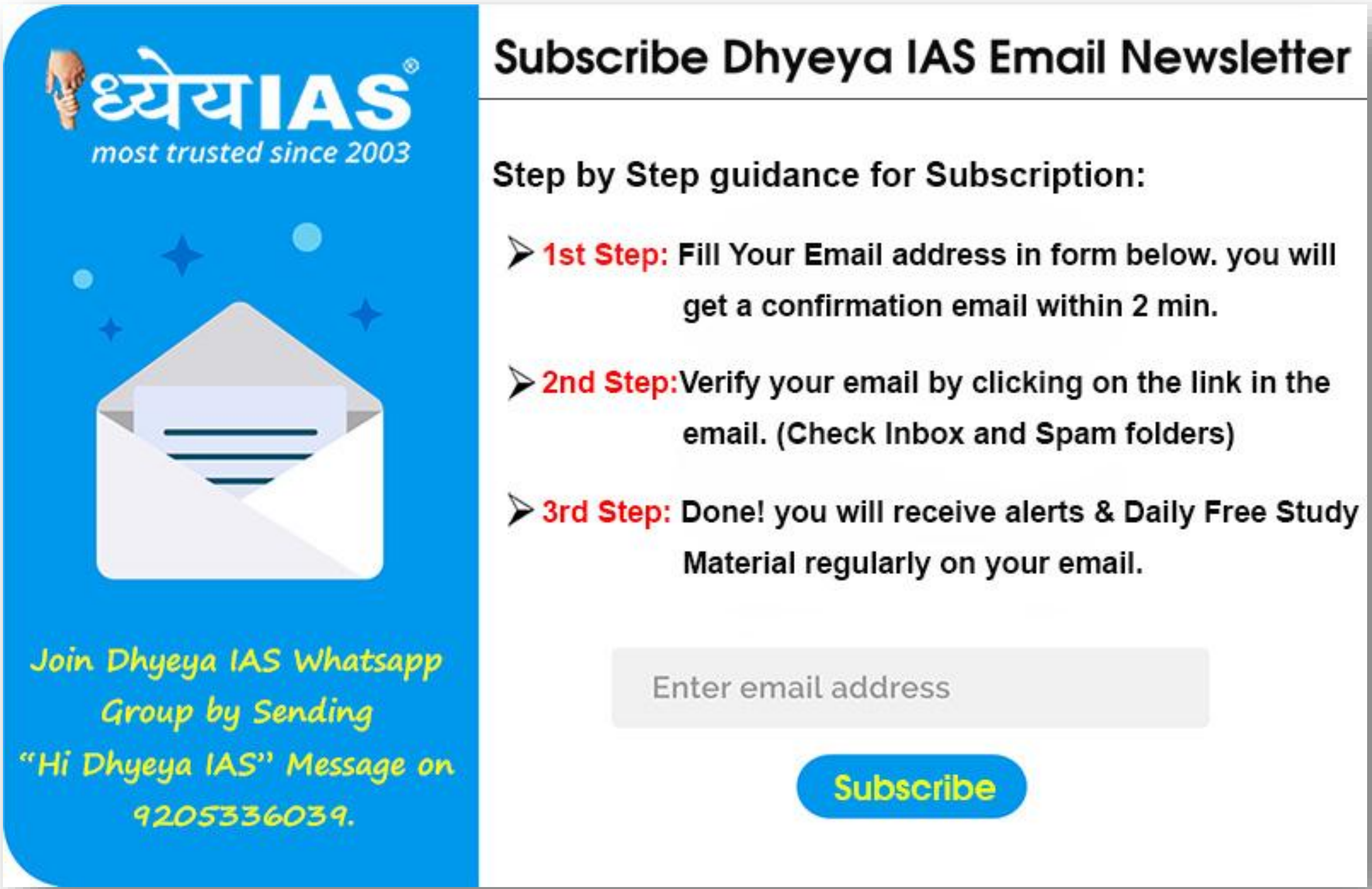

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com